दैनिक
साधना एक्सप्रेस

वर्ष-4 | अंक -249 | sadhnaexpress@gmail.com | भोपाल, गुरूवार, 3 सितंबर, 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य - 2 रुपये | www.sadhnaexpress.com

न्यूज ब्रीफ

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी | इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडेय और अन्य लोग अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है.

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस एकमात्र दस्तावेज का सहारा लिया, वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक लेटर था. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इस लेटर से याचिका में लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है.

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले को सुनने पर संदेह जताया था, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी शिकायत पहले से ही केंद्र सरकार के पास लंबित है. हालांकि, याचिकाकर्ता के जोर देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई की और उनके द्वारा पेश किए गए कागजातों की जांच की. याचिकाकर्ता का दावा था कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटेन में 'बैकऑप्स लिमिटेड' नाम की कंपनी बनाई थी, जिसमें उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता ब्रिटेन के कंपनी रजिस्ट्रार या किसी भी सरकारी रिकॉर्ड से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए.

कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. हाईकोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के वकील भी अदालत में मौजूद थे.

बागी सांसदों ने नोटिस का जवाब देने का मांगा समय

नई दिल्ली, एजेंसी | टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार (2 सितंबर) को उन 20 बागी सांसदों पर निशाना साधा है, जिन्होंने सांसदी रद्द करने की याचिकाओं के संबंध में जारी नोटिसों का जवाब देने के लिए और समय मांगा है. इस पर मोइत्रा ने कहा कि तय समय में जवाब न दे पाना यह दिखाता है कि वे जानते हैं कि उन्होंने गलती की है. आरोप लगाया कि ये सांसद टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वे NCPI और बीजेपी के गठबंधन के साथ चले गए. उनके पास अपने खिलाफ लगे आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं है.

मोइत्रा ने कहा कि बागी सांसदों के इस रवैये ने उनकी राजनीतिक चालों को उजागर कर दिया है. उनके मुखौटे उतर गए हैं. उनकी बेशर्मी और विश्वासघात सबके सामने है. टीएमसी सांसद का यह बयान तब सामने आया है, जब एक दिन पहले ही टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा था कि 20 बागी सांसदों ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से उनकी अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं पर जारी नोटिसों का जवाब देने के लिए लोकसभा सचि वालय से तीन सप्ताह का समय मांगा है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मोइत्रा ने कहा, 'हमने भाजपा से गठबंधन करने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की हैं.

भगवान श्रीकृष्ण के जहां-जहां चरण पड़े, उन्हें श्रीकृष्ण तीर्थ के रूप में विकसित कर रही राज्य सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन कभी आसान नहीं रहा, जिन्हें जन्म लेते ही मार डालने का प्रयास किया गया हो, ऐसे शिशु का कान्हा से विश्व को श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान देने वाले श्रीकृष्ण वंदे जगतगुरु की उपाधि पाने तक का जीवन बेहद संघर्षमय और कठिन परिस्थितियों में बीता। निराशा की घनघोर परछाइयों के बावजूद उन्होंने चुनौतियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और अपने जीवन लोक कल्याण के लिये का सदुपयोग किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने कभी मोह नही रखा। जीवन में जिस व्यक्ति विशेष और वस्तु से उनका सामना हुआ, एक बार वहां से लौटने के बाद दोबारा वे किसी से नहीं मिले। सर्वविदित है कि विश्व के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान भी योगीराज भगवान श्रीकृष्ण के मुखारविंद से ही निकला। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण 64 कलाओं, 14 विद्या और 18 पुराणों में निष्णात थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार की शाम रविन्द्र भवन में आयोजित भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पर केन्द्रित रासलीला समारोह में उपस्थित दर्शकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां राधा-कृष्ण की सजीव झांकी में राधा-कृष्ण बने सुधि और सुघढ़ कलाकारों की विशेष आरती उतारी और उनसे आशीष पाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रासलीला समारोह में दूरदराज से आए कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा सभी को हलषष्ठी और जन्माष्टमी की अग्रिम बधाई दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का मध्यप्रदेश से गहरा नाता रहा। वे मध्यप्रदेश आकर यहीं शिक्षित-दीक्षित होकर कान्हा से भगवान श्रीकृष्ण बने। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं, राज्य सरकार उन स्थलों को चिन्हित कर उन्हें श्रीकृष्ण तीर्थ के रूप में विकसित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं 3 सितम्बर को द्वारिका (गुजरात) भ्रमण पर जा रहे हैं। रासलीला समारोह में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यपालिक अध्यक्ष श्री रघुनंदन शर्मा, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री श्रीराम तिवारी, संचालक संस्कृति श्री एनपी नामदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।

संस्कृति विभाग द्वारा रविन्द्र भवन के मुक्ताकाश मंच में सात दिवसीय 'रासलीला समारोह' का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जा रहा है। समारोह में प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल्यकाल की मनोहारी लीलाओं को सौंदर्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शक इन लीलाओं को देखने एवं देश के सुविख्यात भजन गायकों के भक्ति गायन को सुनने पहुंच रहे हैं। संस्कृति विभाग द्वारा प्राचीन लोककला परम्परा को राज्य स्तरीय आयोजन से प्रदर्शित करने का उद्देश्य युवा पीढ़ी से जुड़ाव एवं आमजन तक इसका प्रचार-प्रसार करना है।

वॉटर सिक्योरिटी को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा- 'राज्य मिलकर करेंगे काम'

नई दिल्ली, एजेंस ी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (2 सितंबर 2026) को राष्ट्रीय जल विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि सम्मेलन में तय किए गए समयबद्ध और क्रियान्वयन योग्य बिंदुओं की लगातार समीक्षा और निगरानी होनी चाहिए.

जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. यह प्रधानमंत्री की परिकल्पना के तहत आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलनों की पहली सीरीज है, जिसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सामूहिक भागीदारी बढ़ाना है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन केवल एक बार होने वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी सिफारिशों पर निरंतर समीक्षा और फॉलो-अप की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.

पीएम मोदी ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों को जल प्रबंधन के प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर दिया. साथ ही, शहरी निकायों के लिए भी ऐसे चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया. पीएम मोदी ने जल बचाने वाली आधुनिक तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराने के लिए प्रदर्शनी और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि भारतीय निर्माता और अन्य हितधारक प्रभावी समाधान विकसित कर सकें.जनभागीदारी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने जल उत्सव अभियान चलाने का सुझाव दिया, जिससे लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े.

उन्होंने जलाशयों की नियमित डी-सिल्टिंग को अभियान का हिस्सा बनाने और इसके लिए स्पष्ट मानक और एसओपी तैयार करने की बात कही. बांध सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने हर मानसून से पहले पूरी तैयारी, सुरक्षा मानकों के पालन और स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी जल और बांध सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल करने पर जोर दिया.

खगंतक-243 का सफल परीक्षण

नई दिल्ली, एजेंसी | भारतीय वायुसेना ने देश में विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खगंतक-243 का ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। परीक्षण में हथियार ने तय मानकों और उद्देश्यों को पूरा किया, जिससे इसके विकास कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है।

जेएसआर डायनेमिक्स द्वारा तैयार यह प्रणाली विमान को लक्ष्य के बिल्कुल ऊपर पहुंचे बिना दूर से प्रहार करने की क्षमता देने के उद्देश्य से विकसित की गई है।

भारतीय वायुसेना ने स्वदेश में डिजाइन और विकसित किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (एलआरजीबी) खगंतक-243 का सफल ड्रॉप परीक्षण किया है।

सीएम विष्णु देव साय - बारिश की हर बूंद सहेजने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी

रायपुर, एजेंसी | बारिश की हर बूंद को सहेजने और उसे धरती के भीतर पहुंचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने देश के सामने जनभागीदारी का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है. जल शक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. राज्य के पांच जिले भी जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाने में सफल रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों और जनभागीदारी आधारित प्रयासों की जानकारी राष्ट्रीय मंच पर साझा की.

इस सम्मेलन के 'कैच द रेन' सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण तथा पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी. इस सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल सहित विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को केवल शासकीय योजनाओं और जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रखा है. किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को इससे जोड़कर इसे व्यापक जनअभियान का स्वरूप दिया गया है.

गाड़ी तेज चलाना अपराध नहीं - दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी | कोर्ट ने पाया कि गवाह के शरीर पर किसी तरह के खरोंच या चोट के निशान होने का कोई सबूत नहीं था. इतना ही नहीं हादसे के बाद उसका मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में एक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल वाहन की तेज रफ्तार को आधार बनाकर चालक को रैश या लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तेज रफ्तार और ओवर स्पीड अपने आप में सापेक्ष शब्द हैं. किसी चालक को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसकी ड्राइविंग वास्तव में लापरवाही या खतरनाक तरीके से की गई थी.

जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार की उस अपील को खारिज करते हुए की जिसमें 2009 के सड़क हादसे में एक महिला की मौत के मामले में टेंपो चालक को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी. चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाना और 304ए यानी लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया गया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि गाड़ी तेज गति से चलाने के लिए ही बनाए गए हैं. महज इसलिए कि वाहन तेज रफ्तार में था यह नहीं माना जा सकता कि चालक रैश या लापरवाह था. कोर्ट ने कहा कि किसी वाहन की स्पीड को परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए.

इस मामले में एक गवाह ने दावा किया था कि वह सड़क के बाई ओर साइकिल चला रहा था और सामने से आ रहे टेंपो ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी. हालांकि कोर्ट ने गवाह के बयान और मेडिकल व मैकेनिकल साक्ष्यों में विरोधाभास पाया.

कोर्ट ने पाया कि गवाह के शरीर पर किसी तरह के खरोंच या चोट के निशान होने का कोई सबूत नहीं था. इतना ही नहीं हादसे के बाद उसका मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया था.

मंदिर गिराने वालों पर कार्रवाई की मांग - रणधीर जायसवाल

नई दिल्ली, एजेंसी | पाकिस्तान में करीब सौ साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने की खबरों पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह घटना दिखाती है कि पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर बर्बरता की जा रही है. मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार इस मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.

MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'पाकिस्तान के नारोवाल जिले के सिराज गांव में एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के विध्वंस की भयावह खबरों से हम बेहद चिंतित हैं. हम एक सदी पुराने अल्पसंख्यक पूजा स्थल के खिलाफ बर्बरता के इस निंदनीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि पड़ोसी मुल्क के अधिकारियों की उदासीनता के चलते इस पुराने मंदिर की रक्षा करने में उनकी नाकामी चिंताजनक है.

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा, 'इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कितने असुरक्षित हैं और उनके धर्म की आजादी और उनके पूजा-स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

राम मंदिर को मिला पहला सीईओ, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा निभायेंगे ये जिम्मेदारियां

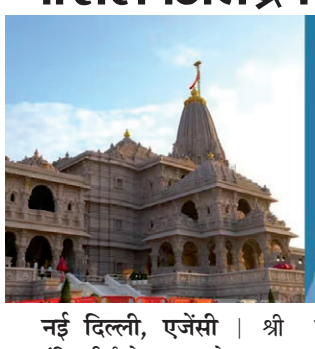

नई दिल्ली, एजेंसी | श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उसका पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मिल गया है. सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लग गई है. इसकी आधिकारिक घोषणा ट्रस्ट की प्रेस वार्ता में होगी.

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अपनी नियुक्ति के दिन से तीन वर्षों तक सीईओ पद पर रहेंगे. वह इसी वर्ष अप्रैल में भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए थे.

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 38 वर्षों तक वायुसेना में सेवा दी है. वह लड़ाकू विमान पायलट, कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट के रूप में काम कर चुके हैं. मिश्रा, गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर, साल 1999 में कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभा चुके हैं.

मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थित देवरिया जिले के निवासी हैं. NDA खड़कवासला के छात्र रहे चुके पूर्व एयर मार्शल के पास 3 हजार घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव है.

ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 5500 से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे. इसमें से 18 के नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे. शॉर्टलिस्ट लोगों से खान-पान, रहन-सहन और हिन्दू धर्म से जुड़ी मान्यताओं को लेकर कई अहम सवाल पूछे गए थे.

क्या होगी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की जिम्मेदारी? - राम मंदिर के CEO की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंदिर का प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी प्रबंधन का जिम्मा संभालना होगा. इसके अलावा वह राम मंदिर के

बता दें सीईओ पद के लिए ट्रस्ट द्वारा तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी. कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े शामिल थे.

दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद आदित्य ठाकरे के साथ ही शिवसेना यूबीटी की भी मुश्किलें बढ़ना तय है

मुंबई , एजेंसी | शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिशा सालियान मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दे दिया है। हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि उसने आदित्य ठाकरे या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं दिया है। अब यह पूरी तरह CBI की जांच और जुटाए जाने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ संदेह के पर्याप्त आधार बनते हैं या नहीं।

हम आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमय मौत के करीब छह साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मामले की CBI जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तत्काल CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच किसी अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी से कराने को कहा गया है।

मस्जिद के पास छप्पर में छिपाकर रखे थे 270 तोते, पश्चिम बंगाल भेजे जाने थे, वन विभाग ने तस्करों से कराए मुक्त

कुशीनगर, एजेंसी | कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में वन विभाग और प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 270 जीवित तोतों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इन पक्षियों को एक छप्पर में छिपाकर रखा गया था और भोर में इन्हें पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान भागने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पहले भी इसी रास्ते से तोतों की खेप पश्चिम बंगाल भेजे जाने की जानकारी दी है। वन विभाग अब पूरे तस्करी नेटवर्क की पड़ताल में जुटा है।

पड़रौना रेंज की टीम बीती रात क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान अकबरपुर टोला बड़वा छापर में बड़ी संख्या में तोतों को अवैध रूप से रखे जाने की सूचना मिली। जिला प्रभागीय वनाधिकारी वरुण सिंह के निर्देश पर कसया, पड़रौना और खड्डा रेंज के कर्मचारियों के साथ प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने रात करीब साढ़े दस बजे अकबरपुर टोला बड़वा छापर में मस्जिद के पास स्थित एक छप्पर पर छापा मारा। यहां बड़ी संख्या में तोते पिंजरों और अन्य साधनों में रखे मिले।

वन विभाग के अनुसार, बरामद तोतों में अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इन तोतों को स्थानीय स्तर पर करीब एक से डेढ़ हजार रुपये में खरीदा जाता है और पश्चिम बंगाल में अधिक कीमत पर बेचने के लिए भेजा जाता है। आरोपी ने पहले भी इस मार्ग से तोतों की खेप भेजे जाने की बात स्वीकार की है। इससे वन विभाग को तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

संयुक्त टीम ने सभी 270 तोतों को सुरक्षित रेस्क्यू कर पड़रौना रेंज के सुपुर्द कर दिया है। वन विभाग की ओर से पक्षियों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। परीक्षण के बाद नियमानुसार उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बांधी अस्पताल में राखी

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

(राजेश नीरस) रक्षा सूत्र राखी का धागा राष्ट्र के लिए समर्पित हर उस व्यक्ति के प्रति स्नेह, सम्मान और कृतज्ञता का बंधन है। इसी भाव से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मार्गदर्शन एवं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे के नेतृत्व में प्रदेशभर में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें कार्यकर्ता भाइयों, महिला एवं पुरुष सफाई कर्मचारियों, स्कूल शिक्षक-शिक्षिकाओं, अस्पताल कर्मचारियों, साधु-संतों, ऑटो रिक्शा चालकों एवं पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर उनके प्रति स्नेह, सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। इसी क्रम में शासकीय सिविल अस्पताल गाडरवारा में अधीक्षक डॉ. उपेंद्र वस्त्रकार एवं स्टाफ को राखी बांध मिठाई खिलाकर नगर की जनस्वास्थय व्यवस्था के लिए उनके प्रति स्नेह, सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेत्री बसंती पालीवाल, पार्षद पूजा तिवारी, सुषमा साहू, खुशी राय आदि कार्यकर्ता बहनें उपस्थित रहीं। इनके द्वारा राष्ट्र एवं समाज की सुरक्षा में समर्पित हर प्रहरी को नमन किया गया।

नगर पालिका द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

(राजेश नीरस) विगत दिवस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद गाडरवारा द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला में स्वच्छता को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय में स्वच्छता विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय की सभी छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और स्वच्छता के महत्व, उसके लाभ और दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। छात्राओं ने अपने निबंधों के माध्यम से स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया।प्रतियोगिता के उपरांत उत्कृष्ट लेखन करने वाली छात्राओं को नगर पालिका परिषद गाडरवारा द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करने और अपने परिवार व मोहल्ले के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी एवं शाला स्टाफ उपस्थित रहा।

जगदीश ससानी बने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(राजेश नीरस) जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नई नियुक्तियां की गई हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटैल की स्वीकृति के उपरांत जिला संगठन मंत्री दीवान शैलेन्द्र सिंह ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को अनुमोदित किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की सहमति से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सतीश सैनी ने कांग्रेस के निष्ठावान नेता पूर्व पार्षद जगदीश सासानी को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। श्री सासानी लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं और सक्रिय रूप से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी इस नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं उनके शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाइयां दी हैं और आशा व्यक्त की है कि उनके अनुभव से संगठन को नई मजबूती मिलेगी।

नगर मे 5 करोड़ रूपयों की लागत से बनेगा वॉटर सप्लाई सिस्टम

नगर में निर्बाध जलापूर्ति किये जाने हेतु जारी है पानी टंकी निर्माण एवं पाईप लाईनों को विस्तार

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

(राजेश नीरस)* नगर में निर्बाध जलापूर्ति किये जाने एवं निकाय पर बोझ बन रहे लाखों रूपयों की राशि के बिजली बिलों को बोझ कम करने के लिये पानी की टंकी निर्माण कार्य एवं पाईप लाईनों को विस्तार किया जा रहा है। चुंकि नगर की विस्तृत पाईप लाईने एवं पानी की टंकी काफी पुरानी हो चुकी है। जिसे दृष्टिगत रखते हुये नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर में जलापूर्ति सुचारू किये जाने एवं भविष्य में 2055 तक निर्बाध जलापूर्ति किये जाने के लिये अमृत 2.0 योजना के तहत पांच करोड़ रूपयों की राशि से गाडरवारा में 20 लाख लीटर की पानी की टंकी का निर्माण एवं क्लियर वॉटर डीआई 12 इंच पाईप लाईन,

ड्रिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन एवं नल कनेक्शन के विस्तार के लिये राशि आबंटित की जाकर कार्य किया जा रहा है। आगामी समय में नगर में संचालित नलकूप जिनकी संख्या 65 हैं, को बंद किया जाना है एवं नगर में सम्पूर्ण जलापूर्ति नई पाईप लाईन एवं नई पानी की टंकियों से किया जाना है। नलकूप बंद होने से नगर पालिका परिषद को बिजली के बिलों में 80 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे की अनावश्यक आर्थिक भार से निकाय को मुक्ति मिल सकेगी। इस कार्य को पूर्ण होने में एक साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कार्य की गति को देखते हुये लक्ष्यानुरूप समय में कार्य पूर्ण होने का अनुमान है। नगरवासियों को पुरानी पाईप लाईन एवं पुरानी पाईप लाईन से निजात मिलेगी और पानी का दुरूपयोग भी कम हो सकेगा। क्योंकि उक्त योजना से निर्धारित समय और निर्धारित मात्रा में जलापूर्ति की जाएगी।

जिला स्तरीय शालेय थ्रो बॉल प्रतियोगिता संपन्न, विद्यार्थियों ने किया दमदार प्रदर्शन

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(राजेश नीरस) गत दिवस स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सत्र 2026-27 की जिला स्तरीय शालेय थ्रो बाल अंडर 19 आयु वर्ग बालक / बालिका प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय पीएमश्री शासकीय कन्या नवीन उ मा विद्यालय में किया गया। इस प्रतियोगिता में अंडर 19 आयु वर्ग के जिले के चांवरपाठा, साईंखेड़ा ब्लॉक सहित अन्य जगहों के छात्र छात्राओं ने सहभागिता करते हुए अपने जौहर दिखाए एवं दमदार प्रदर्शन किया । प्रतियोगिता उपरांत संभाग स्तरीय स्पर्धा हेतु छात्र छात्राओं का चयन उनके अच्छे प्रदर्शन के आधार पर किया गया। इस आयोजन को संपन्न कराने में कन्या नवीन स्टॉफ सहित पीटीआई मुकेश पटैल,विक्रम शर्मा, अजय सोनी, आदित्य द्विवेदी राबिन सिंह, आकाश कौरव,ज्योति धानका,वैशाली बिजोरिया आदि निर्णायक मंडल की अहम भूमिका रही ।

छोटेलाल कौरव को सेवानिवृत्ति पर दी विदाई

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(राजेश नीरस) गत दिवस चीचली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम घोघरा की शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक छोटेलाल कौरव का सेवानिवृत्ति पर विदाभिनंदन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। माँ सरस्वती पूजन से शुरू हुए इस कार्यक्रम में चीचली बीआरसी डीके पटैल, संकुल प्राचार्य ओमप्रकाश कौरव, सत्यम ताम्रकार और सभी शिक्षको ने श्री कौरव को शाल, श्रीफल एवं उपहार भेंटकर विदाई दी। अंत में श्री कौरव ने सभी के सहयोग के लिए आभार जताया।

चरित्र और साँस ही अभिनय की आत्मा हैं अशुतोष राणा

» एनएसडी की गाडरवारा अभिनय कार्यशाला में मास्टर क्लास,

» प्रशिक्षुओं को अभिनय की बारीकियों से कराया अवगत

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(ब्यूरो राजेश नीरस) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), नई दिल्ली के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत तथा रंगसरोकार नाट्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में गाडरवारा में संचालित एक माह की प्रस्तुति-परक अभिनय कार्यशाला में विगत दिवस सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं रंगकर्मी अशुतोष राणा ने प्रशिक्षु अभिनेताओं के लिए विशेष मास्टर क्लास आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने अभिनय, चरित्र निर्माण तथा अभिनेता के आंतरिक अनुशासन पर विस्तार से अपने अनुभव साझा किए।

अपने संबोधन में अशुतोष राणा ने कहा कि 'चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है, जब कोई देख नहीं रहा होता। प्रतिष्ठा समाज की दृष्टि में बनती है, जबकि चरित्र हमारे एकांत में लिए गए निर्णयों से निर्मित होता है। महान चरित्र कभी स्वयं का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपने आचरण से प्रकट होता है।' उन्होंने कहा कि रंगमंच केवल अभिनय की कला नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और सत्य के साथ जीने की साधना है। अभिनेता जितना अपने भीतर के सत्य से जुड़ता है, उतनी ही प्रामाणिकता से वह मंच पर किसी दूसरे पात्र का जीवन जी पाता है।

मास्टर क्लास के दौरान उन्होंने अभिनय में साँस (Breath) की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि साँस ही अभिनेता की ऊर्जा, भाव, लय और संवाद की वास्तविक आधारशिला है। उन्होंने विभिन्न व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को समझाया कि नियंत्रित और सजग श्वास अभिनय को अधिक स्वाभाविक, प्रभावशाली और जीवंत बनाती है। उन्होंने कहा कि अभिनय केवल संवाद बोलना नहीं, बल्कि शरीर, मन और साँस के सामंजस्य से भावों का सृजन करना है।

अशुतोष राणा ने आगे अभिनेता की तैयारी, पात्र के मनोविज्ञान, एकाग्रता, कल्पनाशक्ति, संवेदनशीलता, अवलोकन क्षमता, मंचीय अनुशासन, संवाद की स्वाभाविकता तथा आंतरिक लय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षुओं को नियमित अध्ययन, निरंतर अभ्यास और जीवन के सूक्ष्म अनुभवों से सीखने की प्रेरणा दी।

मास्टर क्लास के दौरान प्रशिक्षु कलाकारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा अभिनय संबंधी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। प्रतिभागियों ने इसे अपने प्रशिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सत्र बताया।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला गाडरवारा में युवा कलाकारों को अभिनय, वॉइस एवं स्पीच, शरीर संचालन, रंगमंचीय खेल, दृश्य विश्लेषण तथा नाट्य प्रस्तुति का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कार्यशाला का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर की रंगमंचीय शिक्षा उपलब्ध कराना तथा भारतीय रंगपरंपरा के मूल्यों से जोड़ना है।

सार समाचार

हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानती मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल :–आठ साल पहले हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए पांच साल की समयसीमा तय की थी। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि बड़े पैमाने पर अतिथि शिक्षकों को लगाकर स्थायी व्यवस्था नहीं की जा सकती, इसलिए नियमित भर्ती के जरिए पद भरे जाएं। इसके बावजूद प्रदेश के स्कूलों की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी करीब 70 हजार अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। स्थायी भर्ती नहीं होने से अभ्यर्थियों और अतिथि शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी और अतिथि शिक्षक मुख्य रूप से 20 से 30 वर्ष की आयु के हैं। जनवरी से अब तक भोपाल समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द स्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।

मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनेंगे कोगजे

भोपाल :-गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को उनके नाम की सिफारिश की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में करीब तीन महीने से स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। 2 जून 2026 से जस्टिस विवेक रूसिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम संभाल रहे हैं। जस्टिस कोगजे ने वर्ष 1993 में वकालत शुरू की थी और गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों में पैरवी की है। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को नियमित मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल को भी नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश हुई है।

बिना बीमा वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

भोपाल :-मध्यप्रदेश में बिना वैध बीमा सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब बिना बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने की व्यवस्था लागू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई बैठक में इस नई व्यवस्था को हरी झंडी दी गई। प्रदेश में कुल करीब 1.75 करोड़ पंजीकृत वाहनों में से लगभग 35 प्रतिशत यानी करीब 61 लाख वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बैठक में तय किया गया कि पहले एक जिले में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सड़क हादसों में मौतों को कम करने के लिए संचालित जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का दायरा भी 6 से बढ़ाकर 9 जिलों तक किया गया है। इसमें अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं।

सत्ता के लिए विपक्ष का यूसीसी होगा चुनावी हथियार

भोपाल :–मध्य प्रदेश की सियासत में अब चुनावी समीकरण को लेकर गर्माहट शुरू हो चली है। एक और ओरछा में बीजेपी का महामंथन जारी है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावी मुद्दों को लेकर सक्रिय हो चली है। इलेक्शन मोड के दौरान कांग्रेस सामान्य नागरिक संहिता के खिलाफ बड़ा कैंपेन खड़ा करेगी। साथ ही लोगों से वादा किया जाएगा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो ष्टष्ट को खत्म किया जाएगा।दरअसल, यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने यूसीसी को एक पक्षीय करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी दिग्गज यूसीसी की खिलाफत कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि असमानता का कानून है। जो प्रदेश का बड़ा मुद्दा होगा। इसे चुनाव समेत अपनी चुनावी रणनीति में प्रमुखता से शामिल किया जाना भी तय है।समानता के नाम पर असमानता, असमाजिकता का कानून- कांग्रेसकांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ विक्रम चौधरी ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता से संविधान की हत्या का रास्ता निकाला गया है। न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने वाला यह कानून है बल्कि संविधान की मूल विचारधारा समानता के भी विपरीत है। एक पार्टी, एक निशान, एक झंडा, एक संविधान की बात करने वाली बीजेपी जातिगत मतभेद का बड़ा प्रपंच रच रही है। लिहाजा पार्टी इन्हें इलेक्शन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में शामिल करेगी।तुष्टिकरण के नाम कांग्रेस, उन्हें चाहिए तीन तलाक के बाद हलाल - बीजेपीवहीं कांग्रेस की इस कवायद पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है और करना चाहती है। कांग्रेस तीन तलाक हलाला और अल्पसंख्यक वर्ग के भले के लिए कभी बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस का सच जनता के सामने है, जिसका जवाब बीते लोकसभा, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिलता रहा है।

ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचें : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल । उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों की निर्धारित समय पर उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अस्पतालों में निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ चिकित्सकों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की नियमित मॉनीटरिंग की जाए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता सीधे तौर पर मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी है। इसलिए ड्यूटी में लापरवाही या निर्धारित समय पर अनुपस्थिति को लेकर प्रभावी निगरानी आवश्यक है।बैठक में विभाग में चल रही विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। श्री शुक्ल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक विशेषज्ञ मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

भोपाल-इंदौर-उज्जैन में लागू होगा जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम

एमपी में सडक हादसों पर सरकार का बड़ा प्लान

भोपाल । मध्य प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार अब हादसों के कारणों की गहराई से पड़ताल कर सुधारात्मक कदम उठाएगी। प्रदेश के धार, सतना, रीवा, सागर, जबलपुर और खरगोन में संचालित ह्यजीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्टह्न कार्यक्रम का विस्तार अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन तक किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करना है, जहां बार-बार हादसे हो रहे हैं। प्रत्येक दुर्घटना के स्थान, कारण और परिस्थितियों का विश्लेषण कर संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बाद सडक की डिजाइन, यातायात व्यवस्था और जन-जागरूकता से जुड़े सुधार किए जाएंगे।

मंत्रालय में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सडक सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति सप्रे ने दुर्घटनाओं और मौतों में प्रभावी कमी लाने के लिए ह्यफोर ईह्न इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एनफोर्समेंट और एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सडक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने पर भी जोर दिया गया।

फिटनेस सेंटर की जांच में मिली बड़ी गड़बड़ी

सडक सुरक्षा समीक्षा के दौरान भोपाल के बायपास स्थित ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण में एक वाहन की फिटनेस प्रक्रिया के दौरान गंभीर विसंगति सामने आई। फिटनेस तकनीशियन ने वाहन को पास बताया, लेकिन सिस्टम में वही वाहन हेडलाइट और हॉर्न की कमी के कारण फेल दिखाई दे रहा था। इस पर समिति अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि जब तक वाहन की पूरी जांच की रिपोर्ट सिस्टम में अपडेट नहीं हो जाती, तब तक उसे फिट घोषित नहीं किया जाना चाहिए। फिटनेस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निर्धारित जांच पूरी किए बिना किसी अनफिट वाहन को फिट घोषित नहीं करने के निर्देश दिए गए।

पशुओं से होने वाले हादसों पर भी बनेगी योजना

सडकों पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां बनाने का सुझाव दिया गया है। इन समितियों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने पर विचार होगा। इसके लिए लघु और दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर उन्हें समय-सीमा में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीमा नहीं तो ईंधन नहीं का पायलट

गैर-बीमित वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश के एक जिले में ह्यबीमा नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सबसे अधिक गैर-बीमित वाहनों वाले जिले का चयन होगा। पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे और उन्हें वाहन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकने की व्यवस्था की जा सके।

छह महीने में 800 मौतें कम होने का दावा

प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में औसतन हर साल करीब 13 हजार लोगों की मौत होती है। हालांकि, 2026 के पहले छह महीनों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में सडक हादसों में होने वाली मौतों में करीब 800 की कमी दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों में दुर्घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने में औसतन 16 मिनट लग रहे हैं, जिसे और कम करने पर जोर दिया गया है।

राशन दुकानों पर अब अफसरों की नजर

भोपाल। भोपाल में सरकारी राशन दुकानों की व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत के मुताबिक दुकानों के स्थान बदलने की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को परेशानी न हो। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई समय-सीमा समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं करने पर कोलार तहसील के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी को समन्वय कर आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती स्कूलों में सह-स्थापित करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल निपटारा नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का अगला शिविर बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

---

40 करोड़ श्रद्धालुओं पर हाईटेक निगरानी; उज्जैन में बनेगा कमांड सेंटर

सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा में पहली बार सेना की एंट्री

भोपाल:- सिंहस्थ 2028 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना के बीच मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। इस बार दुनिया के बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल सिंहस्थ की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय सेना का तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) उज्जैन में भीड़ और अपराध प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीकी सिस्टम उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। सिंहस्थ जैसे विशाल जनसमूह वाले आयोजन में भारतीय सेना के तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञता का इस्तेमाल पहली बार किए जाने की तैयारी है। इसके लिए उज्जैन में एक कमांड सेंटर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है, जहां विभिन्न तकनीकी प्रणालियों से मिलने वाले इनपुट की निगरानी की जा सकेगी।के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग और एमसीटीई महू के बीच नवंबर 2025 में अनुबंध हुआ था। इसके बाद दो दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। इन बैठकों में एमसीटीई ने सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन और अपराध नियंत्रण के लिए अपनी तकनीक उपलब्ध कराने पर सहमति दी थी।

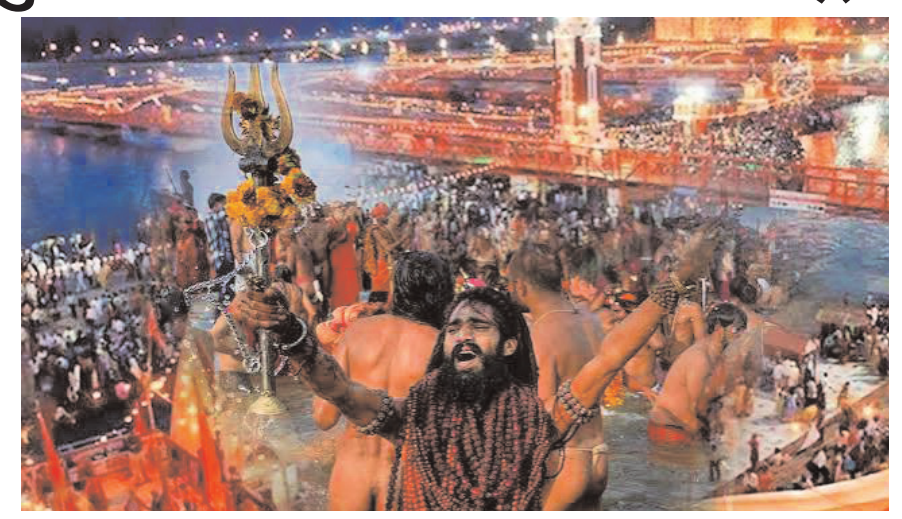

वाहन की पहचान कुछ सेकंड में

एमसीटीई के पास मौजूद व्हीकल रिकग्निशन सिस्टम सिंहस्थ की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आधारित इस सिस्टम के जरिए कैमरे वाहन का नंबर पढकर उपलब्ध डेटाबेस से उसका मिलान कर सकेंगे।

साइबर हमले से भी सुरक्षित रहेंगे सिस्टम

सिंहस्थ में बड़ी संख्या में आईटी उपकरण, कैमरे और डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे में साइबर सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। एमसीटीई का साइबर सुरक्षा सिस्टम इन तकनीकी उपकरणों को हैकिंग और साइबर खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगा।

चेहरे से संदिग्धों पर नजर

सुरक्षा व्यवस्था में फेस रिकग्निशन सिस्टम के इस्तेमाल की भी तैयारी है। इसके जरिए कैमरों से प्राप्त तस्वीरों का उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान में सहायता ली जा सकती है।

प्रयागराज से लिया जाएगा तकनीकी अनुभव

प्रयागराज सिंहस्थ में भी बड़े पैमाने पर एआई और स्मार्ट सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वहां संदिग्ध और अपराधियों की पहचान के लिए एआई आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग किया गया।

एमपी में बज गया चुनावी बिगुल, नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव 29 सितंबर को

8 सितंबर से नामांकन, 15 सितंबर तक आवेदन, 3 अक्टूबर को आ जाएंगे अधिकांश नतीजे

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी। आयोग ने सोमवार को उपचुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव के मुताबिक 8 सितंबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र जमा होने शुरू हो जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 18 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पंचायतों के लिए मतदान का समय सुबह से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इतने पदों पर होगा चुनाव

पंचायत उपचुनाव के तहत जिला पंचायत के 7, जनपद पंचायत के 28 और सरपंच के 110 पदों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा 4,090 पंच पदों पर भी चुनाव कराया जाएगा। नगरीय निकायों में नगर परिषद सुसनेर, नगर पालिका टीकमगढ़ और नगर परिषद कुक्षी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इसके साथ ही अलग-अलग नगरीय निकायों में 26 पार्षद पदों के लिए भी मतदान कराया जाएगा। इनमें इंदौर नगर निगम के वार्ड 58 और 60, ग्वालियर नगर निगम का वार्ड 5 तथा सागर नगर निगम का वार्ड 11 सहित अन्य रिक्त वार्ड शामिल हैं।

3 और 5 अक्टूबर को आएंगे परिणाम

पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतगणना होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव की मतगणना 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित होंगे। इस तरह उपचुनाव के साथ प्रदेश में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।

कर्नल सोफिया मामले में विजय शाह को बड़ी राहत

राज्यपाल ने अभियोजन की अनुमति न देने के कैबिनेट प्रस्ताव पर लगाई मुहर

भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत मिली है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राज्य मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं देने की सिफारिश की गई थी। सोमवार देर रात इस पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने आई। दरअसल, 25 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन की अनुमति नहीं दी गई है। यह मामला उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा है, जो विजय शाह ने 11 मई 2025 को इंदौर जिले के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान की थी। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में की गई उनकी टिप्पणी को लेकर व्यापक विवाद हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ ऋक्रक्र दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया, जिसने मामले की क्लोजर रिपोर्ट का रास्ता खुला 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया है। इसी सुनवाई के दौरान एसआईटी के अधिकारी ने कहा था कि यदि कैबिनेट की ओर से अभियोजन की अनुमति नहीं मिलती है तो जांच एजेंसी अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में आगे एसआईटी की ओर से मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने की संभावना है।

विकास और बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई गति, मंत्रि-परिषद ने 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को दी मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लगभग 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास के लिए ह्यविकसित भारत (ग्रामीण): वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजनाह्न के क्रियान्वयन हेतु 29 हजार 619 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया।

दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 2 हजार 973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना स्वीकृत की गई। इससे प्रदेश में

... को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में पश्चिम भोपाल बायपास के 35.61 किलोमीटर लंबे 4-लेन मार्ग के निर्माण के लिए 3 हजार 774 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। वहीं मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के 67.116 किलोमीटर लंबे 4-लेन मार्ग के निर्माण के लिए 3 हजार 272 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरजीपीवी का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन पृथक प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य संस्थाओं में मशीन एवं उपकरणों के अनुरक्षण के लिए 488.41 करोड़ रुपये तथा चिकित्सा संस्थानों की विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 915.77 करोड़

इसके अलावा मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय विभाग के जिला कार्यालयों के लिए 21 पद तथा निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा

संचालन के लिए 20 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। किसानों के हित में पंजीकृत कृषकों से मूंग उपज के 60 प्रतिशत तक उपार्जन किए जाने के

मप्र में दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक संबल प्रदान करने 2,973 करोड़ की योजना मंजूर

26 हजार गांवों तक फैलेगा सहकारी डेयरी नेटवर्क

भोपाल। प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक संबल प्रदान करने और डेयरी उद्योग के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से राज्य कैबिनेट ने 2,973 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि के विशेष पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन, संकलन और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) क्षमता का विस्तार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार स्वीकृत कुल राशि में से केवल दूध प्रसंस्करण क्षमता को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए 1,547

... किया गया है। सरकार ने अगले पांच वर्षों के भीतर प्रदेश में सहकारी दुग्ध समितियों के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में जहां सहकारी दुग्ध समितियों का दायरा केवल 7,331 गांवों तक सीमित है, वहीं योजनाबद्ध तरीके से इसे बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक ले जाया जाएगा। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और सीमांत दुग्ध उत्पादक किसानों को सीधे सहकारी नेटवर्क से जोडकर उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलाना आसान होगा। संकलन, प्रसंस्करण और बिक्री क्षमता में रिकॉर्ड

... मंजूर की गई इस दूरगामी योजना के तहत डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं-दूध के दैनिक एकत्रीकरण की क्षमता को वर्तमान 12 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। दूध की प्रोसेसिंग क्षमता को मौजूदा 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाया जाएगा। उपभोक्ताओं तक शुद्ध दूध पहुंचाने के लिए पैकेटबंद दूध की दैनिक बिक्री को 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन करने का

|| संपादकीय ||

एससीओ के मंच से चीन और पाकिस्तान को एक साथ धोकर मोदी ने दुनिया की वाहवाही लूट ली

एससीओ शिखर सम्मेलन में वैसे तो सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने संबोधन में तमाम तरह के मुद्दे उठाये लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में शामिल मुद्दों की विविधता और सबको साथ लेकर चलने के जज्बे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साथ ही तमाम अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक भी यह देखकर हैरान हैं कि कैसे मोदी ने मंच पर साथ मौजूद चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया तो वहीं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सवाल पर चीन को भी आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद पर मोदी ने दो टूक कहा कि जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं और आतंकवाद को अपनी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंक कभी किसी की रणनीतिक संपत्ति नहीं बन सकता। वहीं कनेक्टिविटी के नाम पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौते को अस्वीकार करते हुए उन्होंने चीन को भी साफ संदेश दिया।

किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी मौजूदगी को महज औपचारिक भागीदारी तक सीमित नहीं रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के 25 वर्षों की यात्रा को अगले 25 वर्षों की दिशा तय करने के अवसर में बदलते हुए भारत का स्पष्ट एजेंडा सामने रखा। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्च्युनिटी के जरिये मोदी का संदेश था कि अब केवल घोषणाओं और संवाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना होगा।

प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे धारदार हिस्सा आतंकवाद पर था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ कार्रवाई केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आतंकवादी वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ, सुरक्षित ठिकानों और पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड को स्वीकार करने से साफ इंकार किया। यह संदेश ऐसे मंच से आया, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्वयं मौजूद थे।

भारत की कूटनीतिक उपलब्धि यहीं समाप्त नहीं हुई। एससीओ के 25 वर्ष पूरे होने पर स्वीकार की गई बिश्केक डिक्लेरेशन ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती दी। घोषणा और शिखर सम्मेलन के अन्य फैसलों में आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुरक्षा चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए यूनिवर्सल सेंटर संबंधी नियमों को मंजूरी देना सदस्य देशों के बीच समन्वय और सूचना आदान-प्रदान को मजबूत करने वाला कदम है।

भारत के लिए विशेष महत्व की बात यह भी रही कि अंग्रेजी को एससीओ के संस्थागत ढांचे में शामिल करने की दिशा में प्रगति हुई। साथ ही भारत द्वारा आगे बढ़ाई गई कई पहलों जैसे- एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, यंग साइंटिस्ट फोरम और यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव को भी बिश्केक डिक्लेरेशन में स्थान मिला। यह संकेत है कि भारत अब एससीओ में केवल सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठाने वाला देश नहीं, बल्कि संगठन के बौद्धिक, सांस्कृतिक और संस्थागत भविष्य को आकार देने वाला सक्रिय साझेदार बन रहा है।

मोदी ने अपनी विदेश नीति की व्यापक सोच को भी भाषण में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यूरेशिया की सुरक्षा और शांति का संबंध अफगानिस्तान की स्थिरता से जुड़ा है और भारत वहां विकास तथा मानवीय सहायता जारी रखेगा। पश्चिम एशिया के संघर्षों का उदाहरण देते हुए उन्होंने आगाह किया कि आज की दुनिया में किसी एक क्षेत्र का युद्ध उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उसका असर ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है, जिसका सबसे अधिक बोझ ग्लोबल साउथ को उठाना पड़ता है। इसलिए भारत का स्पष्ट मत है कि युद्धों और तनावों का समाधान रणभूमि पर नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने नशे के कारोबार को भी क्षेत्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी केवल अपराध नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय स्थिरता पर हमला है। इस संदर्भ में एससीओ के तहत सुरक्षा, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और नारकोटिक्स से निपटने के लिए बनाए जा रहे केंद्रों को प्रभावी और त्वरित कार्रवाई का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। इस तरह आतंकवाद और नार्को-टेररिज्म के खिलाफ भारत की चिंता को व्यापक एससीओ एजेंडे से जोड़ने में सफलता मिली।

कनेक्टिविटी पर भी मोदी का संदेश उतना ही स्पष्ट और कूटनीतिक रूप से अहम था। भारत बाजारों को जोड़ने, व्यापार बढ़ाने और विकास के नए रास्ते खोलने वाली सभी पहल का समर्थन करता है, लेकिन ऐसी किसी भी परियोजना के लिए सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। प्रधानमंत्री का यह संदेश चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल और विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है। भारत लंबे समय से इस परियोजना का विरोध करता रहा है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। ऐसे में मोदी ने बिना किसी देश या परियोजना का नाम लिए एससीओ मंच से साफ कर दिया कि कनेक्टिविटी और विकास के नाम पर किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने सड़क, रेल और हवाई संपर्क बढ़ाने के अलावा कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

तीसरे स्तंभ यानि अपॉर्च्युनिटी के जरिए मोदी ने एससीओ सहयोग को आम लोगों से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि युवाओं के लिए कितने अवसर बने, उद्यमियों के लिए कितने नए बाजार खुले, किसानों को तकनीक से कितना लाभ मिला और नागरिकों का जीवन कितना बेहतर हुआ। मोदी ने जोर दिया कि एससीओ सहयोग केवल सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि पीपुल-ड्रिवन पार्टनरशिप बनना चाहिए। इसी दिशा में भारत इस वर्ष पहले एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम की मेजबानी करेगा।

इसके अलावा, शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातों ने भी भारत की सक्रिय कूटनीति को मजबूत किया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, जबकि लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसौलिथ के साथ द्विपक्षीय संबंधों और संपर्क को मजबूत करने पर बातचीत हुई। ये मुलाकातें बताती हैं कि बहुपक्षीय मंचों पर भारत की रणनीति केवल भाषण देने की नहीं, बल्कि समानांतर रूप से द्विपक्षीय संबंधों का नेटवर्क मजबूत करने की भी है।

बहरहाल, बिश्केक एससीओ समिट में मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, दोहरे मापदंडों को चुनौती दी, संप्रभुता आधारित कनेक्टिविटी का सिद्धांत दोहराया और भारत की सांस्कृतिक व युवा-केंद्रित पहलों को एससीओ के एजेंडे में स्थापित किया। उनका संदेश साफ था कि "शेयर्ड जियोग्राफी" को "शेयर्ड अपॉर्च्युनिटीज" में बदलना होगा, विजन को परिणामों में और सरकार-केंद्रित सहयोग को जन-केंद्रित साझेदारी में परिवर्तित करना होगा। कुल मिलाकर, बिश्केक से भारत ने यही संकेत दिया है कि बदलते यूरेशियाई समीकरणों में वह एजेंडा तय करने वाला देश बन चुका है।

सुर्खियों में रहने के लिए विवादित बयान देने वालीं स्वरा भास्कर को जौहर पर टिप्पणी करना भारी पड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया करारा जवाब

> 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित चर्चा के दौरान स्वरा भास्कर ने पद्मावत के क्लाइमैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि सैकड़ों महिलाओं को जौहर करते देख उन्होंने सोचा कि यदि वह स्वयं कभी यौन हिंसा की शिकार होतीं तो फिल्म का संदेश उन्हें क्या महसूस कराता।

फिल्म पद्मावत के जौहर दृश्य को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। दिल्ली में आयोजित 'Woman, Life, Freedom' कार्यक्रम में उनकी टिप्पणियों का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उन पर रानी पद्मावती और जौहर करने वाली महिलाओं को अपमानित करने के आरोप लगे। विवाद बढ़ा तो स्वरा सामने आईं और कहा कि उनकी बात को "पूरी तरह गलत तरीके से अनुवादित और प्रसारित" किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्वरा ने वास्तव में क्या कहा। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर उनकी सार्वजनिक टिप्पणियां बार-बार ऐसे विवादों का रूप क्यों ले लेती हैं, जिनके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ती है कि "मेरा मतलब वह नहीं था"?

हम आपको बता दें कि 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित चर्चा के दौरान स्वरा भास्कर ने पद्मावत के क्लाइमैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि सैकड़ों महिलाओं को जौहर करते देख उन्होंने सोचा कि यदि वह स्वयं कभी यौन हिंसा की शिकार होतीं तो फिल्म का संदेश उन्हें क्या महसूस कराता। स्वरा का तर्क था कि ऐसी प्रस्तुति किसी बलात्कार पीड़िता को यह महसूस करा सकती है कि जीवित रहना कम सम्मानजनक है और मृत्यु को चुनना अधिक "बहादुरी" है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे समाज में, जहां यौन हिंसा गंभीर समस्या है, फिल्मों को महिलाओं की "पवित्रता" को उनके जीवन से अधिक मूल्यवान दिखाना चाहिए। उन्होंने जौहर दृश्य में एक गर्भवती महिला के शॉट पर भी आपत्ति जताई और इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी।

विवाद तब बढ़ा जब सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया गया कि स्वरा ने रानी पद्मावती और जौहर करने वाली महिलाओं को "कायर" कहा है। इसके बाद स्वरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो रानी पद्मावती को कायर कहा और न ही जौहर करने वाली अन्य महिलाओं को। स्वरा ने कहा कि उनका मूल आशय यह था कि फिल्म का दृश्य आधुनिक दौर के यौन हिंसा पीड़ितों तक कौन-सा संदेश पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला बलात्कार के बाद जीवित रहती है, तो उसे कभी यह महसूस नहीं कराया जाना चाहिए कि उसके जीवन या सम्मान का मूल्य कम हो गया है।

यहां सवाल उठता है कि क्या स्वरा इतिहास के सबसे कठिन संदर्भ को नजरअंदाज कर रही हैं? स्वरा भास्कर का यह कहना कि बलात्कार या यौन हिंसा के बाद भी महिला का जीवन, सम्मान और अस्तित्व पूरी तरह मूल्यवान है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण और आधुनिक मानवीय तर्क है। किसी भी पीड़िता को आत्महत्या, आत्मदाह या मृत्यु के लिए प्रेरित करना न तो स्वीकार्य है और न ही उसका महिमामंडन किया जाना चाहिए। लेकिन पद्मावत के जौहर प्रसंग और आधुनिक बलात्कार पीड़िताओं की परिस्थितियों को एक ही पैमाने पर रख देना इतिहास की जटिलताओं को अत्यधिक सरल बना देता है।

जौहर की ऐतिहासिक चर्चा युद्ध, पराजय, सामूहिक हिंसा, दासता और विजेता की सत्ता के भयावह संदर्भ में होती है। उस समय महिलाओं के सामने सिर्फ यौन हिंसा का खतरा नहीं, बल्कि बंदी बनाए जाने, दासता, जबरन हरम में भेजे जाने और जीवन भर विजेता की संपत्ति बनकर रहने जैसी परिस्थितियों का भय भी मौजूद बताया जाता है। ऐसे में जौहर को केवल "महिलाओं को अपनी पवित्रता बचाने के लिए मरने का संदेश" कहकर खारिज कर देना क्या उस ऐतिहासिक त्रासदी को पर्याप्त रूप से समझना है?

शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद रहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी स्वरा भास्कर के तर्क का विरोध करते हुए बहस में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा है। उनका कहना था कि युद्ध और आक्रमण जैसी चरम परिस्थितियों में मृत्यु, दासता या विजेता के हरम में जबरन जीवन बिताने के बीच महिलाओं द्वारा लिया गया निर्णय उनकी व्यक्तिगत राय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी का तर्क मूलतः यह है कि उस निर्णय से असहमति हो सकती है, उसके ऐतिहासिक विवरणों पर बहस हो सकती है, लेकिन उन महिलाओं के सामने मौजूद परिस्थितियों को नजरअंदाज कर उनके फैसले को हल्के ढंग से देखना उचित नहीं है।

देखा जाये तो यही इस विवाद का केंद्रीय प्रश्न है कि क्या आज की सुरक्षित, आधुनिक और संवैधानिक दृष्टि से सदियों पुराने युद्धकालीन निर्णयों का मूल्यांकन करना पर्याप्त है? इतिहास का अध्ययन करते समय यह याद रखना आवश्यक है कि अतीत के लोगों के पास वे विकल्प नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। आधुनिक समाज में आत्मदाह का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन जौहर की ऐतिहासिक व्याख्या करते समय उसके संदर्भ को समझना आवश्यक है। जौहर को केवल "पवित्रता बचाने के लिए आत्महत्या" के रूप में देखना अधूरा दृष्टिकोण है। युद्धकालीन परिस्थितियों में यह सामूहिक रूप से विजेता के सामने समर्पण न करने और दासता को स्वीकार न करने की त्रासद प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए यह कहना कि जौहर करने वाली महिलाएं "जीना नहीं चाहती थीं" या उनका निर्णय केवल स्त्री-विरोधी सामाजिक मानसिकता का परिणाम था, यह उस समय के हालात की वास्तविकता को नकारना है।

हम आपको यह भी बता दें कि स्वरा भास्कर का पद्मावत से विवाद नया नहीं है। जनवरी 2018 में फिल्म की रिलीज के बाद उन्होंने निर्देशक संजय लीला भंसाली को एक खुला पत्र लिखा था। उस पत्र में भी उन्होंने फिल्म के जौहर दृश्य और महिलाओं की गरिमा को यौन शुचिता से जोड़ने पर सवाल उठाए थे। पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती की भूमिका निभाई थी, जबकि शाहिद कपूर और रणवीर सिंह भी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म मलिक मोहम्मद जायसी की 16वीं शताब्दी की रचना पद्मावत से प्रेरित थी और रिलीज से पहले ही बड़े विवादों में घिर चुकी थी। फिल्म का जौहर दृश्य उसके सबसे चर्चित दृश्यों में शामिल रहा और आज, वर्षों बाद भी, वही दृश्य बहस का केंद्र बना हुआ है। बहरहाल, पद्मावत और जौहर पर बहस जारी रह सकती है और जारी रहनी भी चाहिए। लेकिन बहस का आधार न तो इतिहास का अंध-महिमामंडन होना चाहिए और न ही आधुनिक दृष्टि के नाम पर अतीत की जटिल परिस्थितियों को खारिज कर देना चाहिए।

• नीरज कुमार दुबे

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

पहाड़ी जीवन के खतरे

कृत्रिम बांधों और ग्लेशियरों के खतरे तमाम हिमालयी राज्यों में मंडरा रहे हैं, तो नेपाल की घटना ने हिमाचल को भी सचेत किया है। प्रदेश के बांधों में एक चौथाई गाद का ठहरना जलक्षमता के भंडारण पर असर डाल रहा है, तो सडक़ मार्गों में सुरंगों के अलावा जल परियोजनाओं में सुरंगों के जरिए पानी को ले जाने का प्रबंध किया गया है। जाहिर तौर पर पर्वतीय आंचल में विकास के मायने तेजी से बदले हैं और मानवीय जरूरतों के कारण निर्माण के मानदंड भी औपचारिकता ही निभा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बांधों में जमती गाद को प्रमुख दुश्मन मानते हुए इसे हर तरह से हानिकारक माना है। प्रदेश की जल वितरण प्रणाली और विद्युत आपूर्ति का खाका भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न चुनौतियों को नजरअंदाज कर रहा है। हिमाचल के शहरी इलाकों पर बढ़ता आबादी का घनत्व आधारभूत सुविधाओं के जोखिम बढ़ा रहा है। हर वर्ष नदी-नालों के करीब बस्तियों पर डाका डालती प्रकृति की नजर को न समझे, तो रामपुर के आसपास, सडक़ों के किनारे उठती इमारतों या मैदानी इलाकों में जल भराव के सामने दयनीय स्थिति के कोप भाजक बन जाएंगे। बरसात में बांधों से पानी छोडऩे का गुनाह कई बार नूरपुर के इलाकों को पस्त कर चुका है, तो हर साल ऊना में रुकने वाले पानी से जल प्रबंधन के नई योजनाएं सामने नहीं आई हैं। यह सब इसलिए भी कि हिमाचल में ग्राम एवं नगर योजना कानून के तहत जल निकासी की दिशा में कोई नया प्रयोग नहीं किया। हिमाचल की पारंपरिक नदियों के जल बहाव को हम केवल बरसाती पानी या बाढ़ के दौरान ही देखते हैं, जबकि सबसे बड़ा अध्ययन नदियों के बेसिन्स पर होने चाहिएं। हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ग्लेशियर तीव्रता से पिघल कर नई झीलों को जन्म दे रहे हैं। सौ के करीब ऐसी संवेदनशील झीलें बन चुकी हैं, जो अपने आकार और पानी के दबाव के कारण विस्फोटक क्षमता रखती हैं।

हिमाचल की सभी नदियों के स्रोत पहले भी पाराछू झील की तरह खतरे पैदा कर चुके हैं। सतलुज नदी के तटीय क्षेत्रों में भूगर्भीय हलचल ने बार-बार खतरे चिन्हित किए हैं, तो बाकी नदियां भी बाढ़ के संकेतों के साथ जल प्रलय का नासूर लेकर चलती हैं। ऐसे में नेपाल की घटना ने हिमालयी राज्यों की नीतियों में खास तवज्जो देने की नसीहत दी है। कायदे से भारतीय संदर्भों में हिमालयी राज्यों के न तो जलाधिकार सुनिश्चित हुए हैं और न ही जल आबंटन के राष्ट्रीय मानक किसी सर्वमान्य आधार पर पुष्ट हुए हैं। हम फसल की प्रतीक्षा में मानसूनी बादलों का हिसाब करते हैं, लेकिन बांधों के जलस्तर से ऊपर पिघलते ग्लेशियरों के नाज नहीं देखते। पानी के सारे खतरे पहाड़ी जीवन के आसपास छोड़ दिए जाते जबकि इसकी राष्ट्रीय विवेचना जरूरी है। देश की अनेकों नदियां उन परिस्थितियों से निकलती हैं, जिनके मध्य भोटेकोशी या त्रिशुली नदी को भयावह आचरण ओढऩे की तोहमत मिली है। केंद्र सरकार द्वारा जल प्रबंधन के नीतिगत फैसले तथा जल सिंचाई की परियोजनाएं मैदानी इलाकों की राजनीति को तृप्त करती हैं, जबकि असली चुनौती छोटी-बड़ी हजार के करीब झीलों तथा नदियों के तटीय आवरण में मानवीय गतिविधियों से है। हिमालयी क्षेत्र के कैचमेंट क्षेत्रों में विस्तृत अध्ययन, चौकसी, अलर्ट सिस्टम के अलावा नदी-नालों का तटीकरण जरूरी हो जाता है। इन खतरों की चुनौतियों से रू-ब-रू हिमालयी क्षेत्रों के लिए केंद्र में स्वतंत्र विभाग तथा मंत्रालय का सृजन करना होगा।

टेक्नोलॉजी

AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है. ज्यादातर लोग अब अपने काम के लिए एआई का सहारा लेने लगे हैं. इसी के साथ ही अब कई सारे एआई चैटबॉट मौजूद हैं जो लोगों के लिए अलग-अलग काम करते हैं. इसी कड़ी में एक स्टडी सामने आई है जहां बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा एआई के इस्तेमाल से लोगों के दिमाग पर खराब असर पढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला.

AI से ज्यादा बातचीत का इंसानों की भाषा पर असर - रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक AI चैटबॉट्स के साथ बातचीत करता है तो संभव है कि वह धीरे-धीरे अपनी बात रखने का तरीका बदलने लगेगा. वजह ये हो सकती है कि AI को साफ, व्यवस्थित और सीधे निर्देश ज्यादा आसानी से समझ आते हैं.

मसलन, अगर कोई व्यक्ति बार-बार AI कस्टमर सर्विस चैटबॉट का इस्तेमाल करता है तो उसे ये एक्सपीरिएंस हो सकता है कि छोटी, साफ और सीधे मुद्दे पर कही गई बात का जवाब बेहतर मिलता है. ऐसे में वह इंसानों से बात करते समय भी अनजाने में इसी तरह संवाद करने लगेगा.

क्या है Robotoid Humanness? - AI & Society में पब्लिश एक नए स्टडी पेपर में रिसर्सर्च ने इस बदलाव को Robotoid Humanness नाम दिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान सचमुच रोबोट बन जाएंगे. बल्कि ये एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें लोग मशीनों के लिए अपनी लैंग्वेज, नेचर और खुद को पेश करने के तरीके को ज्यादा बेहतर बनाने लगते हैं.

AI और इंसान के बीच बन सकता है फीडबैक लूप - आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोधकर्ताओं ने इस प्रोसेस को एक तरह के फीडबैक लूप के रूप में समझाया है. AI हमारी पिछली बातचीत और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जवाबों को व्यक्तिगत बनाने की कोशिश करता है. वहीं, यूजर भी AI के जवाबों को देखकर अपनी बातचीत का तरीका बदल लेता है. ये प्रोसेस लगातार चलती रहे तो दोनों पक्ष एक-दूसरे के नेचर के अनुसार ढलते जाते हैं. बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को तीन स्टेज में बांटा है.

AI यूजर की एक तस्वीर तैयार करता है

यूजर भी AI के हिसाब से खुद को ढाल सकता है

इंसानों और AI के बीच सबसे बड़ा अंतर - आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोधकर्ताओं के मुताबिक, इंसानों के बातचीत करने में काफी अंतर होता है. इंसान आपकी बात से कई बार असहमत भी हो सकता है या फिर आपकी बात को चैलेंज भी कर सकता है. लेकिन दूसरी तरफ, AI सिस्टम पैटर्न, डेटा, अनुमान और व्यक्तिगत रिएक्शन पर काफी हद तक काम करते हैं. इसीलिए एआई से ज्यादा बातचीत इंसानों को भी उनके तरीके से बात करने के लिए तैयार कर सकती है.

जनरल नॉलेज

कहां से आया रेड कारपेट कल्चर, पहली बार किसके लिए बिछाया गया था इसे?

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयजित शंघाई सहयोग संगठन समिट में दुनिया के कई बड़े नेता एक ही मंच पर नजर आए. ऐसे हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में नेताओं के औपचारिक स्वागत और आगमन के दौरान नजर आने वाला रेड कारपेट सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि सम्मान और खास दर्जे का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रेड कारपेट की यह परंपरा शुरू कहां से हुई और सबसे पहले इसे किसके लिए बिछाया गया था? आइए जानते हैं रेड कारपेट कल्चर का इतिहास.

हजारों साल पुरानी है रेड कारपेट कहानी - आज रेड कारपेट का नाम लेते ही दिमाग में हॉलीवुड, फिल्म स्टार्स और अवॉर्ड समारोह आते हैं. असल में इसकी शुरूआत प्राचिन समय में हुई थी. रेड कारपेट के बारे में सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख 458 ईसा पूर्व में लिखे गए प्राचीन यूनानी नाटक Agamemnon में पता चलता है. इसे मशहूर ग्रीक नाटककार Aeschylus ने लिखा था. नाटक में ट्रॉय युद्ध से जीतकर लौटे राजा अगामेमनन के स्वागत के लिए उनकी पत्नी क्लाइटेमनेस्ट्रा एक लाल रंग की भव्य राह बिछाती है.

स्वागत के लिए बिछाया गया था रेड कारपेट - कहानी में क्लाइटेमनेस्ट्रा अपने पति अगामेमनन का भव्य स्वागत करती है और उनके घर तक पहुंचने के लिए लाल रंग की कालीननुमा राह बिछवाती है. इस स्वागत के पीछे सिर्फ सम्मान नहीं था, इतनी भव्य राह पर चलना उस समय देवताओं के लिए उपयुक्त माना जाता था. यहीं से रेड कारपेट का एक महत्वपूर्ण अर्थ सामने आता है कि सामान्य लोगों से अलग किसी व्यक्ति को विशेष सम्मान देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. हालांकि यह उल्लेख केवल एक नाटक में है.

जेम्स मोनरो के लिए भी बिछाया गया था रेड कारपेट - आधिकारिक तौर पर रेड कारपेट 1821 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के स्वागत में बिछाया गया था. बाद में 19वीं और 20वीं सदी में रेड कारपेट का चलन शाही कार्यक्रमों और औपचारिक आयोजनों में आम हो गया. रेड कार्पेट को वैश्विक स्तर पर पहचान अभिनेता और ग्लैमर से जुड़ने के बाद मिली. खासकर ऑस्कर जैसे कार्यक्रमों से यह काफी लोकप्रिय हो गया.

लाल रंग ही क्यों? - दरअसल, प्राचीन समय से ही लाल रंग को संपन्नता, सम्मान और राजसी वैभव से जोड़कर देखा जाता है. वहीं पूराने समय में लाल रंग को तैयार करना उतना आसान नहीं होता था, जिससे इसे केवल खास और विशेष लोगों के लिए ही तैयार किया जाता था. ऐसे में आम लोगो के लिए इसे पाना मुश्किल होता था.

`मक्खियों संग बाघों को भी नहीं बख्शेंगे', चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी `नई आर्मी' से 100 जनरल हटाए

एजेंसी बीजिंग

चीन में बड़ी हलचल हो रही है। वहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के 100 से ज्यादा जनरलों को हटा दिया है। हाल ही में जिनपिंग ने चीन के वेस्टर्न थिएटर के पूर्व कमांडर जनरल झाओ जोंगकी को हटाया गया, जो जिनपिंग द्वारा हटाए गए 102वें सीनियर कमांडर बन गए। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग अपनी 'नई आर्मी' बना रहे हैं। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जिनपिंग करना क्या चाह रहे हैं। चीन में चल क्या रहा है? क्या वाकई में जिनपिंग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के संस्थापक रहे माओ जेडोंग की तर्ज पर खुद को और ताकतवर बना रहे हैं। क्या चीन में ये हलचल भारत के लिए टेंशन की बात है? इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानेंगे। द प्रिंट के एक लेख के मुताबिक, 2015 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) में जनरल बनने के लिए हर अफसर का रूस में युद्ध की ट्रेनिंग लेना एक जरूरी शर्त थी। यह लेख चीन पर पैनी नजर रखने वाले मेजर जनरल(रि.) मनदीप सिंह (SM, VSM) ने लिखा है। स्टालिन ने 1937-38 में रेड आर्मी में बड़े पैमाने पर सफाया किया। इसके पीछे उनका शक और हर तरह के प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने का इरादा था। उन्होंने पांच में से तीन सोवियत मार्शल, पंद्रह में से तेरह आर्मी कमांडर और 30,000 से 40,000 तक अफसरों को या तो मरवा दिया या जेल में डाल दिया। इसी वजह से जर्मन तानाशाह हिटलर को लगा कि सोवियत सेना एक कमजोर और बिना सिर वाले विशालकाय शरीर जैसी है। इसलिए, 1941 में उसने तेल से समृद्ध काकेशस और स्टालिनग्राद पर कब्जा करने के लिए 'ऑपरेशन बारबारोसा' शुरू किया। आखिरकार, स्टालिन को अपने कुछ जनरलों को रिहा करना पड़ा, उन्हें फिर से बहाल करना पड़ा। युद्ध के समय की कमान देनी पड़ी और जर्मन सेना से लड़ना पड़ा। रूसी सेना ने जर्मनों को रोका और आखिरकार लगभग तीन साल बाद 1944 में उन्हें बुरी तरह हरा दिया। लेख के अनुसार, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति CCP के चेयरमैन और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन के तौर पर राजनीति, पार्टी और सेना के प्रमुख बने, तो उन्होंने PLA को 'वर्ल्ड-क्लास' सेना में बदलने के लिए 'मिलिट्री मामलों में क्रांति' (RMA) का अपना महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। सैन्य पहलुओं के अलावा, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और गुटबाजी की गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति को खत्म करने की भी जरूरत थी। शी ने PLA लीडरशिप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और 'मक्खियों' के साथ-साथ 'बाघों' पर भी कार्रवाई करने का वादा किया, जिसका मतलब था कि वे किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे उनका ओहदा कुछ भी हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'अगर हम बुरी प्रवृत्तियों को पनपने से नहीं रोकते और उन्हें बढ़ने देते हैं, तो यह पार्टी और हमारे लोगों के बीच दीवार खड़ी करने जैसा होगा, और हम अपनी जड़ें, अपनी जीवन-शक्ति और अपनी ताकत खो देंगे'। उन्होंने 'औपचारिकता, नौकरशाही, भोग-विलास और फिजूलखर्ची' जैसी चार बुराइयों के खिलाफ़ एक अभियान शुरू किया और 2012 में इन चार बुराइयों को खत्म करने के लिए 'आठ-सूत्रीय नियम' जारी किए। अगर हम बुरी प्रवृत्तियों को पनपने से नहीं रोकते और उन्हें बढ़ने देते हैं, तो यह पार्टी और हमारे लोगों के बीच दीवार खड़ी करने जैसा होगा, और हम अपनी जड़ें, अपनी जीवन-शक्ति और अपनी ताकत खो देंगे'। जिनपिंग ने सत्ता में आने के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सफाई अभियान शुरू किया। हालांकि, इसके पीछे खुद को और ताकतवर बनाना और सत्ता के प्रतिद्वंद्वियों को निपटाना था। उस समय लोगों को ऊंचे आदर्श पसंद आए थे। पार्टी के दस लाख से ज्यादा सदस्यों को निकाला गया था, और यह सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन 2026 का समय 2012 जैसा नहीं है। किसी भी सिस्टम के लिए यह लगभग नामुमकिन है कि वह 14 लंबे सालों तक भ्रष्ट बना रहे और उसके जनरल बिना किसी नतीजे के डर के अनुशासन और कानून का गंभीर उल्लंघन करते रहें। इसलिए, समस्या कहीं और है। एक्सपर्ट के अनुसार, यह सफाया बड़े पैमाने पर हो रहा है, या यह किसी खास इलाके, ग्रुप या गुट के खिलाफ है? सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के 'चाइना पावर प्रोजेक्ट' के जनवरी 2022 से फरवरी 2026 के बीच चले एक व्यापक अध्ययन में कुछ दिलचस्प और अहम जानकारी सामने आई है। जिनपिंग ने सबसे ज्यादा सफाया सदर्न थिएटर कमांड में किया जिनपिंग के अभियान में सबसे ज्यादा सफाया 'सदर्न थिएटर कमांड' में हुआ है, उसके बाद 'सेंट्रल', 'ईस्टर्न' और 'नॉर्दर्न थिएटर' का नंबर आता है। शी जिनपिंग के चीनी राष्ट्र के पुनरुत्थान के सपने को पूरा करने के लिए ताइवान पर कब्जा करने की जिम्मेदारी इन्हीं तीन कमांड्स की है। किसी राजनीतिक नेता के लिए इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात और क्या हो सकती है कि जिन कमांडरों को यह पवित्र जिम्मेदारी सौंपी गई हो, वे ही गलतियां करने वाले और भ्रष्ट निकलें।

चीन के टैंकर ने पहली बार राफेल जेट के अंदर हवा में भरा तेल, भारत और फ्रांस की बढ़ेगी टेंशन

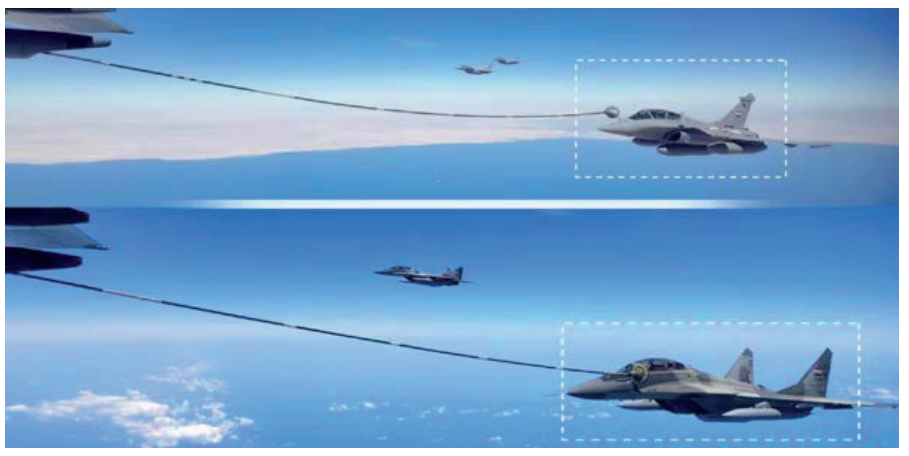

एजेंसी काहिरा

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट और पाकिस्तान के चीनी जे-10 सी फाइटर जेट के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली थी। अब एक साल बाद चीन के टैंकर YY-20 ने राफेल जेट के अंदर हवा में तेल भरा है। इससे पहले राफेल जेट और चीन के जे-16 फाइटर जेट के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। असल में चीन के जे-16 फाइटर जेट और तेल टैंकर YY-20 मिस्र पहुंचे हैं जो राफेल जेट का एक बड़ा बेड़ा रखता है। ऐसा पहली बार है जब चीन के तेल टैंकर ने राफेल जेट के अंदर हवा में ईंधन भरा है। इसकी तस्वीर को खुद मिस्र की वायुसेना ने जारी किया है। इस तस्वीर से न केवल भारत की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि फ्रांस के लिए भी यह झटका है। चीन की सेना ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इसका फोटो शेयर किया है और कहा कि यह दोनों ही बढ़ती इंटरऑपरेबिलिटी को दर्शाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक चीनी तेल टैंकर ने पश्चिमी फाइटर जेट में ईंधन भरा है। चीन ने YY-20 टैंकर को 6 जे-16 फाइटर जेट, वाई-20 ट्रांसपोर्ट प्लेन, KJ-500 AEW&C और अन्य विमानों के साथ मिस्र भेजा है। इसके बाद चीनी विमान यूएई के साथ भी हवाई अभ्यास करेंगे। यह तेल टैंकर ही था जिसकी बदौलत चीन के फाइटर जेट 6000 किमी का सफर करके पहुंचे हैं। यह उनकी पहली तैनाती है। सैन्य विश्लेषक शहरयार पसंददिह ने यूरेशिया टाइम्स से बातचीत में कहा कि अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि चीन का विमान फ्रांस के बनाए राफेल जेट में ईंधन भरने में सक्षम है। इससे पहले चीन के इस तेल टैंकर PLAAF YY-20 ने मिस्र के रूसी MiG-29M में एक अभ्यास के दौरान साल 2025 में तेल भरा था। चीनी टैंकर YY-20 और राफेल दोनों ही probe-and-drogue तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी दुश्मन देशों के विमानों ने हवा में ईंधन भरा है। इससे पहले नवंबर 2024 में अमेरिका के KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट ने मलेशिया के रूसी मूल के सुखोई Su-30MKM विमानों में हवा में ईंधन भरा था। वहीं भारत के राफेल जेट में रूसी मूल के IL-78 तेल टैंकर हवा में नियमित रूप से तेल भरते रहते हैं। चीनी तेल टैंकर का राफेल में तेल भरना इसलिए अहम है कि फ्रांस और भारत दोनों ही ड्रैगन को बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। यही नहीं चीन राफेल की जगह पर अपने जे-10 सी को दुनियाभर के देशों को ऑफर कर रहा है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर राफेल के खलिाफ दुष्प्रचार भी चलाया था।

रूस-चीन के साथ गठबंधन की चर्चा लेकिन भारत क्यों नहीं बनना चाहता किसी गुट का हिस्सा ? पूर्व विदेश सचिव ने बताया

एजेंसी नई दिल्ली

बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। SCO समिट के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी काफी चर्चा रही। मंगलवार पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंगके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। पश्चिम के कुछ देशों में इस बात की चिंता है कि यदि रूस-चीन और भारत (RCI) का कोई गठबंधन बनता है तो इससे पश्चिम देशों खासकर अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल का मानना है कि भारत किसी भी खास गुट में शामिल नहीं होना चाहता।
कंवल सिब्बल का कहना है कि भारत RCI या किसी दूसरे खास गुट में शामिल नहीं होना चाहता। भारत की नीति किसी एक खेमे में रहने की बजाय सभी प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की है। भारत BRICS का संस्थापक सदस्य है और 2017 में SCO में शामिल हुआ। इसका मतलब है कि भारत कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय है जो पश्चिमी देशों के नेतृत्व से अलग है। भारत 2005 से अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करते हुए भी, कई सालों से गैर-पश्चिमी देशों के साथ काम करने में सहज रहा है। भारत जब 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील और उभरते देशों)के हितों की वकालत करता है तो यह भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गैर-पश्चिमी देशों से अलग दृष्टिकोण रखने का ही एक उदाहरण है। कंवल सिब्बल ने कहा कि भारत रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय स्तर पर और BRICS व SCO के सहयोग एजेंडे के तहत, साझा हितों के मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक को संबोधति कयिा। पीएम मोदी ने कहा शिखर सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ, एसीओ की ओर से विकसित बातचीत और सहयोग की मजबूत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप तैयार करने का सही समय है। पीएम मोदी ने भारत के इस रुख को दोहराया कि संघर्षों को युद्ध के मैदान में हल नहीं किया जा सकता और बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

शहबाज शरीफ ने चौतरफा आलोचना के बाद सुधारी गलती, SCO बैठक की PM मोदी वाली तस्वीर पोस्ट की

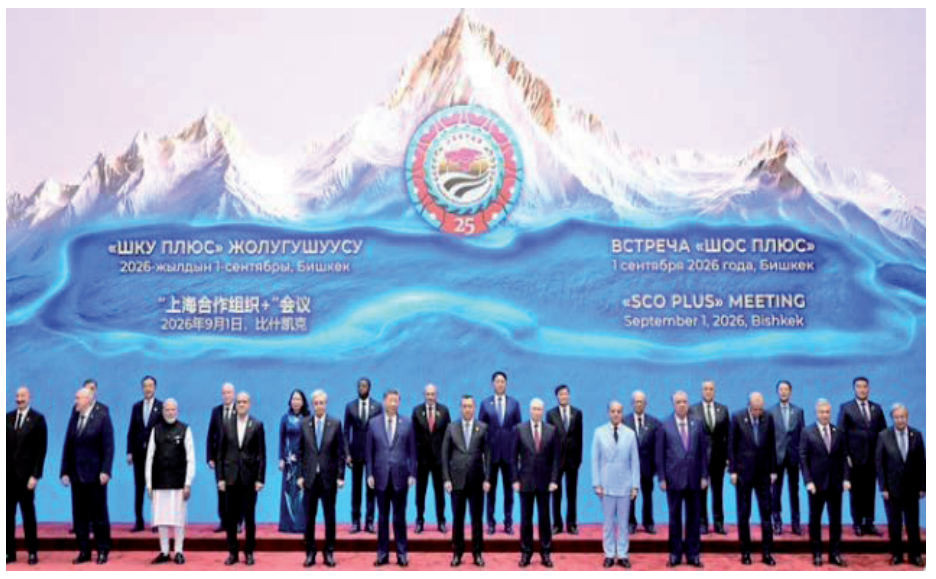

एजेंसी इस्लामाबाद

पाकिस्तान ने हमेशा की तरह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान सोशल मीडिया पर बचकानी हरकत करने के बाद अपनी गलती सुधार ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय और शहबाज शरीफ दोनों ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल से एससीओ समिट की पूरी ग्रुप फोटो को शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी PMO ने ने SCO नेताओं की ग्रुप फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया था। वहीं, पीएम मोदी की पोस्ट की गई ग्रुप फोटो में शहबाज शरीफ समेत सभी नेता दिख रहे थे। पाकिस्तान के पीएमओ ने एक्स पर नया ग्रुप फोटो शेयर करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ 1 सितंबर 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट में SCO+ बैठक के लिए विश्व नेताओं के साथ एक फैमिली फोटो में।" यह फaटो मंगलवार को बिश्केक में SCO समिट के दौरान ली गई थी, जिसमें 10 सदस्य देशों के नेता और विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि एक साथ पोज दे रहे थे। हालांकि, पाकिस्तान के PMO ने सबसे पहले जो SCO की ग्रुप फोटो शेयर की थी, उसमें पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत कुछ अन्य नेताओं की तस्वीरों को क्रॉप कर दिया गया था। कुछ ही

देर बाद, आलोचना होने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पर्सनल X अकाउंट से पूरी ग्रुप फोटो पोस्ट की। पाकिस्तानी PMO के फोटो के क्रॉप किए गए वर्शन को इस तरह से सेट किया गया था कि शहबाज शरीफ ग्रुप के बीच में दिखें। इससे यह दिखाने की कोशिश की गई कि शरीफ ज्यादा अहम जगह पर हैं। हालांकि, वास्तविकता इसके ठीक उलट थी। पाकिस्तान इतने पर भी नहीं माना। फेसबुक पर शहबाज शरीफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी एक वीडियो से पीएम मोदी को हटा दिया गया, जिसमें बिश्केक में SCO नेताओं की राउंडटेबल मीटिंग दिखाई गई थी। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान की बचकानी सोशल मीडिया हरकतों को समझ गए। कई लोगों ने पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा का जवाब देने के लिए पूरी ग्रुप फोटो भी पोस्ट की।

नेपाल में बाढ़ में 20 से अधिक बैंकों की तिजोरियां बहीं, करोड़ों का सोना और नकदी ढूंढ रही पुलिस

एजेंसी काठमांडू

नेपाल में बुधवार को आई भयानक बाढ़ में लापता लोगों को खोजने का काम अब भी जारी है। इस बाढ़ में अब तक 1000 से अधिक लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इससे कहीं अधिक लोग गायब हैं। इस बीच पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती बाढ़ में बहीं बैंकों की 20 से अधिक तिजोरियों (वॉल्ट) की तलाश करना बन रहा है। ये तिजोरियां या तो बाढ़ में बहकर दूर चली गई हैं, या फिर मलबे और गाद के नीचे फंसी हुई हैं। ऐसे में इन तिजोरियों को ढूंढने और सुरक्षित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि लापता तिजोरियों में भारी मात्रा में नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान है। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि वे लुटेरों के हाथ लग सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये वॉल्ट रासुवा, धाडिंग और चितवन सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों के बैंकों के थे। DIG अबी नारायण काफ्ले ने कहा कि लापता लोगों की तलाश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, लेकिन प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और कीमती सामान को सुरक्षित करना भी एक जरूरी काम है। हमारे सहयोगी प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "रासुवा, धाडिंग, चितवन और अन्य जगहों पर बैंक थे जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। उनमें से कई वॉल्ट, जिनमें नकदी और सोना जैसी कीमती चीजें थीं, या तो बह गए या भारी गाद के नीचे दब गए। हमारे जवान अब उन वॉल्ट को खोजने और सुरक्षित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां लोगों ने बहकर आए वॉल्ट को तोड़कर नकदी चुरा ली।" पुलिस ने बैंकों के वॉल्ट को तोड़कर पैसा चुराने के आरोप में 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी धाड़िंग जिले में हुई है। पुलिस के अनुसार, अपर रासुवा इलाके से बहकर आए एक बैंक वॉल्ट से 92 लाख रुपये (NPR) चुराए गए थे। पुलिस कुछ लापता वॉल्ट को खोजने और सुरक्षित करने में भी कामयाब रही है। रविवार शाम को, जवानों ने त्रिशूली में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक की धुंगे शाखा का एक वॉल्ट खोज निकाला। रिपोर्ट के अनुसार, DIG अबी नारायण काफ्ले ने कहा, "रविवार शाम को, हमारे जवान त्रिशूली में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक की धुंगे शाखा के एक वॉल्ट को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। इस काम में उन्हें लगभग आठ घंटे लगे।" पुलिस अधिकारी के अनुसार, बरामद वॉल्ट में 1.5 करोड़ रुपये (NPR) नकद और अन्य कीमती सामान था, जिसमें 50 करोड़ रुपये (NPR) कीमत का सोना भी शामिल था। बाकी तिजोरियों को खोजने का काम जारी एक अलग ऑपरेशन में, पुलिस ने नुवाकोट में कृषि विकास बैंक का एक वॉल्ट भी सुरक्षित किया।

भारतीय वायुसेना का `गेमचेंजर' राफेल जेट स्टील्थ विमानों के आगे `बेकार' है ? फ्रांसीसी रिपोर्ट से उठे सवाल

एजेंसी पेरिस

पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल के बाद भारतीय वायुसेना का विश्वास राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर और बढ़ गया है। राफेल लड़ाकू विमान बेचने में एक वक्त फ्रांस संघर्ष कर रहा था लेकिन भारत से डील ने इस विमान की किस्मत बदल दी। राफेल बनाने वाली डसॉल्ट कंपनी के पास अब इसके इतने ऑर्डर हैं कि डिलीवरी समय पर देने के लिए अलग अलग प्लांट लगाए जा रहे हैं। खुद भारत भी फ्रांस से कम से कम 114 राफेल लड़ाकू विमान और खरीदने जा रहा है और करीब 35-40 अरब डॉलर की डील को लेकर दोनों देशों में फिलहाल बात चल रही है। भारतीय अधिकारी हमेशा से राफेल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट SPECTRA और HAMMER मिसाइलों की क्षमता की जमकर तारीफ करते आए हैं। लेकिन क्या राफेल सचमुच 5th जेनरेशन के स्टील्थ लड़ाकू विमानों जैसे चीनी J-20 या अमेरिका के F-35 के सामने टिक पाएगा? फ्रांसीसी रक्षा विश्लेषकों और वायुसेना की एक इनसाइड रिपोर्ट ने राफेल को लेकर जो जानकारियां दी है उसपर एक नया बहस शुरू होने की संभावना है। इस रिपोर्ट के आने के बाद फ्रांसीसी पायलटों और रक्षा विशेषज्ञों के आकलन और भारतीय दावों के बीच एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। यह रिपोर्ट फ्रांस की वायु और अंतरिक्ष सेना के भविष्य के हवाई युद्ध मॉडल, उनके युद्ध लड़ने की क्षमता और वर्ष 2035 तक के उनके स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये एक रणनीतिक समीक्षा रिपोर्ट है जिसमें फ्रांसीसी वायुसेना को आगे क्या करना चाहिए उसको लेकर सलाह दिए गये हैं। इस रिपोर्ट को फ्रांसीसी वायुसेना के मौजूदा और पूर्व लड़ाकू पायलट, एयरोस्पेस रणनीतिकार और रक्षा विश्लेषकों ने मिलकर तैयार किया है। फ्रांसीसी रिपोर्ट में राफेल को लेकर क्या-क्या कहा गया है?
स्टील्थ विमानों के आगे कमजोर- फ्रांसीसी पायलटों और रणनीतिकारों का मानना है कि 4.5 जेनरेशन का राफेल किसी 5th जेनरेशन स्टील्थ लड़ाकू विमान के खिलाफ पर्याप्त नहीं है। उच्च-तीव्रता वाले युद्ध में राफेल की अपनी सीमाएं हैं। नाटो के लिए सिर्फ सहयोगी की भूमिका- रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा उपकरणों और क्षमताओं के साथ फ्रांसीसी वायुसेना युद्ध के दौरान नाटो की तरफ से सिर्फ सहयोगी भूमिका ही निभा सकती है। क्योंकि दुश्मनों के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने और SEAD मिशन को अंजाम देने (एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त) करने में अकेले राफएल सक्षम नहीं है। राफेल-F5 बहुत जरूरी- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल का F4 स्टैंडर्ड मौजूदा राफेल की क्षमता में थोड़ा सुधार जरूर करेगा लेकिन दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह तबाह करने की वास्तविक क्षमता F5 स्टैंडर्ड के साथ ही आएगी। चिंता की बात यह है कि फ्रांस ने कहा है कि 2035 तक ही राफेल F-5 ऑपरेशनल हो पाएगा। भारत भी कम से कम 24 F-5 खरीदना चाहता है लेकिन अब वो 2035 के बाद ही संभव हो पाएगा हैमर और स्टैंड-ऑफ हथियारों की सीमित क्षमता- इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सिर्फ स्टैंड-ऑफ बम या हैमर जैसे हथियारों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। अत्याधुनिक एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD) जोन में इन हथियारों का प्रभाव सीमित हो जाता है। भारत ने भी हैमर खरीदा हुआ है। फ्रांसीसी रिपोर्ट के उलट भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारी दावा करते हैं कि राफेल स्टील्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ बहुत बढ़िया है और इसकी स्पेक्ट्रा क्षमता एक गेम-चेंजर है। इसीलिए राफेल को लेकर एक नये बहस की शुरूआत होने की संभावना है। फ्रासीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल में कई कमियां हैं खासकर SEAD के एरिया में और क्वांटिटेटिव, जिसमें फ्लीट और स्टॉक लगातार हाई-इंटेंसिटी वाले टकराव से निपटने के लिए काफी नहीं हैं।

एशियन गेम्स से पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, नाहिद राणा हुए टूर्नामेंट से बाहर

नईदिल्ली ■ एजेंसी

जापान की मेजबानी में 19 सितंबर से एशियन गेम्स की शुरुआत हो रही है। इस टूर्नामेंट में इस बार क्रिकेट के मुकाबले भी खेले जाएंगे जिसके लिए हाल ही में शेड्यूल का ऐलान किया गया था। इस टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज नाहिद राणा चोट की वजह से इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (क्रष्टक्र) के अधिकारियों ने सोमवार (31 अगस्त) को साफ किया कि वे आने वाले एशियन गेम्स के लिए तेज गेंदबाज नाहिद राणा के नाम पर विचार नहीं कर रहे हैं।

नाहिद हाल ही में साइड स्ट्रेन की चोट से उबरे हैं और उन्होंने छह हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद नेट में दोबारा गेंदबाजी शुरू की है। बोर्ड उनके साथ कोई जल्दबाजी या जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए उन्हें एशियन गेम्स से आराम देकर अक्टूबर में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज के जरिए मैदान पर वापसी कराने की तैयारी की जा रही है। इस इंजरी की वजह से वह हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से भी बाहर रहे थे। आपको बता दें कि वह जिम्बाब्वे दौरे पर

चोटिल हुए थे।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर ने साफ किया है कि तेज गेंदबाज नाहिद राणा आगामी एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह अभी अपनी रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। बोर्ड उनके साथ कोई जल्दबाजी या जोखिम नहीं उठाना चाहता। हबीबुल ने बताया कि नाहिद पूरी तरह फिट होने के बाद अक्टूबर में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज से मैदान पर वापसी करेंगे। हालांकि, वह उस सीरीज में टेस्ट मैच खेलेंगे या वनडे, यह बाद में तय होगा, लेकिन एशियन गेम्स में उनके न खेलने की बात पूरी तरह पक्की है।

एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 23 जुलाई 2026 की क्ष्20 रैंकिंग के हिसाब से टीमों की रैंकिंग तय कर दी गई है। टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक, निचली रैंकिंग वाली 6 टीमों को पहले आपस में ग्रुप स्टेज के मैच खेलकर नॉकआउट दौर में जगह बनानी होगी। वहीं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टॉप 4 टीमों को अपनी बेहतरीन आईसीसी रैंकिंग का फायदा मिला है और उन्हें सीधे क्वार्टरफाइनल में जगह मिल गई है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपना क्वार्टरफाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेलेगी।

'लक्ष्य मंथन' योगासन प्रतियोगिता में 375 प्रतिभागियों ने दिखाया दमखम

इंदौर ■ निसं

राज्य स्तरीय 'लक्ष्य मंथन योगासन प्रतियोगिता' में प्रदेशभर से आए 375 बाल योग साधकों ने योगासन में अपना कौशल दिखाया। योग आयोग, मध्य प्रदेश शासन के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में प्रतियोगिता का पहला क्वालिफाइंग चरण रविवार को सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कीम नंबर 74, विजय नगर में संपन्न हुआ। 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत और पेयर वर्ग में प्रस्तुतियां दीं। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने कठिन योगासनों का प्रदर्शन करते हुए शुद्धता, संतुलन, लचीलेपन और तकनीक का परिचय दिया। पेयर वर्ग में संगीत की लय के साथ तालमेल और समन्वय के आधार पर प्रस्तुतियां हुईं। राष्ट्रीय स्तर की योग निर्णायक परीक्षा उत्तीर्ण निर्णायक मंडल ने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद नन्दवाल ने बताया कि प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला क्वालिफाइंग चरण पूरा हो गया है। दूसरा चरण 6 सितंबर को इसी स्थल पर होगा। दोनों चरणों से चयनित प्रतिभागी 12 सितंबर को बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में होने वाले फाइनल में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी शौर्य मल्होत्रा, एसडीएम हातोद राजेश सिंह, स्कूल प्राचार्य फादर पायस, क्षेत्रीय खेल अधिकारी हेमंत वर्मा और प्रशांत महंत मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

मुंबई की टीम ने बदला कप्तान; 8 हजार से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिली कमान

नईदिल्ली ■ नगर संवाददाता

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर चयन समिति ने आगामी रणजी सीजन से पहले एक बड़ा फैसला किया है। शार्दुल ठाकुर की जगह अनुभवी सिद्धेश लाड को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक शार्दुल को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कप्तानी से हटाया गया है। वहीं सिद्धेश पिछले सीजन भी शार्दुल की गैरमौजूदगी में टीम के कप्तान बनाए गए थे। पिछले सीजन लाड ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 774 रन ठोके थे।

शार्दुल ठाकुर ने 2025-26 सत्र के लिए अजिंक्य रहाणे की जगह मुंबई की कप्तानी संभाली थी, जिसमें 42 बार की रणजी ट्रॉफी विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई थी। हालांकि, लाड ने अपने बल्ले का जादू दिखाया था। उन्होंने

पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में 8 मैच खेलते हुए 77.40 की औसत से 774 रन बनाए थे जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल था। बता दें कि 34 वर्षीय लाड बीच में मुंबई को छोड़कर गोवा चले गए थे। फिर उन्होंने एक साल की 'कूल ऑफ' अवधि पूरी करने के बाद 2024-25 में मुंबई की टीम में वापसी की थी।

अब वह आगामी रणजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के एक शीर्ष अधिकारी ने लाड की नियुक्ति की पुष्टि की है। रणजी सत्र की शुरुआत 11 अक्टूबर को होगी और मुंबई की टीम अपने पहले मैच में चंडीगढ़ से भिड़ेगी। शार्दुल ठाकुर कप्तानी से हटे हैं लेकिन वह टीम का अहम हिस्सा बने रहेंगे। चयन समिति का मानना है कि शार्दुल को उनके खेल के साथ कप्तानी का दबाव ना दिया जाए और उनका वर्कलोड मैनेज किया जाए।

सिद्धेश लाड के करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 समेत सभी फॉर्मेट में 8 हजार से अधिक रन बनाए हैं। उनके नाम 82 फर्स्ट क्लास मैचों में 5623 रन और 8 विकेट दर्ज हैं।

दो घंटे 51 मिनट में 42 किमी दौड़ पूरी, हैदराबाद मैराथन में बनाया रिकॉर्ड

पहाड़ की बेटी भागीरथी ने लहराया परचम

चमोली ■ निसं

कठिन परिस्थितियों से निकलकर यहां तक पहुंचना उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। उनकी उपलब्धि पहाड़ की उन बेटियों के लिए प्रेरणादायक है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखती हैं।

चमोली जिले के सीमांत वाण गांव की बेटी भागीरथी बिष्ट ने बार फिर उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। 24 वर्षीय भागीरथी ने हैदराबाद में आयोजित मैराथन दौड़ में 42 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ दो घंटे 51 मिनट में पूरी करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तराखंड के दुर्गम गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वालीं भागीरथी की उपलब्धि से देवभूमि में खुशी की लहर है। ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद भागीरथी ने जिस तरह अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया, वह क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा बन गया है।

भागीरथी के कोच सुनील शर्मा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से हैं। अंतरराष्ट्रीय मैराथन एथलीट सुनील ने बताया कि भागीरथी लगातार कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं। इससे पहले भी वह ईरान में आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इसके अलावा, देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित कई मैराथन प्रतियोगिताओं में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है।

कोच ने बताया कि भागीरथी का लक्ष्य केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतना नहीं है। उनका सपना ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर मैराथन दौड़ में गोल्ड मेडल जीतना और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। कोच ने कहा कि भागीरथी में प्रतिभा के साथ मेहनत करने का जज्बा भी है।

कठिन परिस्थितियों से निकलकर यहां तक पहुंचना उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। उनकी उपलब्धि पहाड़ की उन बेटियों के लिए प्रेरणादायक है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखती हैं। वाण गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ भागीरथी का दौड़ का सफर अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। हैदराबाद में जीता गया सिल्वर उनके लिए एक और बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनकी नजरें अब ओलंपिक गोल्ड पर हैं।

व्यापार समाचार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 पर मीडिया को संबोधित किया

10 वर्ष के लक्ष्य के मुकाबले चार वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है

जबलपुर ■ निसं

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। इस अवसर पर सेमीकॉन 2.0 योजना के सभी छह स्तंभों के लिए अधिसूचनाएं जारी की गईं, जो भारत की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह योजना पहले सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से मिली गति को आगे बढ़ाती है और चिप डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग से लेकर उपकरण, सामग्री, अनुसंधान और विकास और प्रतिभा विकास तक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य सेमीकंडक्टर

आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाकर और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करके भारत की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यह योजना 10 श्रेणियों को कवर करने वाले छह स्तंभों के माध्यम से संचालित होगी।

सेमीकॉन 2.0 के अंतर्गत छह मुख्य स्तंभ इस प्रकार हैं: स्तंभ 1 - डिज़ाइन, स्तंभ 2 - मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ - अधिक फैब स्थापित करना, स्तंभ 4 - एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को और अधिक सुदृढ़ बनाना, स्तंभ 5 - अनुसंधान और विकास, स्तंभ 6 - प्रतिभा विकास

स्तंभ1- डिजाइन: श्रेणियां: राष्ट्रीय महत्व और रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए सेमीकंडक्टर आईपी, चिप, सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) और मॉड्यूल का डिजाइन; वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए सेमीकंडक्टर आईपी, चिप और एसओसी का डिजाइन; और तैनाती के लिए सेमीकंडक्टर आईपी/ चिप्स/ एसओसी के लिए तैनाती-लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई)।

स्तंभ 2 - मशीनें और सामग्री: श्रेणी: सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।

स्तंभ 3 - अधिक फैब की स्थापना: श्रेणियां: सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर फैब; कंपाउंड सेमीकंडक्टर /फोटोनिक्स/ सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब/ डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब; और डिस्प्ले फैब।

स्तंभ 4 - एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को और मजबूत करना: श्रेणी: सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा।

स्तंभ 5 - अनुसंधान और विकास: श्रेणी: उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास।

स्तंभ 6 - प्रतिभा विकास: श्रेणी: प्रतिभा विकास। कार्यक्रम के दौरान श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर तैयार करने का अपना लक्ष्य मात्र चार वर्षों में ही हासिल कर लिया है।

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल

नईदिल्ली ■ एजेंसी

आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक 7.8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे रिकॉर्ड संख्या बताया।

31 जुलाई की अंतिम तिथि मुख्य रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उन करदाताओं के लिए थी, जिनकी आय वेतन, मकान संपत्ति, ब्याज या पूंजीगत लाभ जैसे स्रोतों से आती है। वहीं, व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करने वाले और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें 31 अगस्त तक का समय मिला था। इस श्रेणी में फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, छोटे कारोबारी और कई प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जो आमतौर पर आईटीआर-3 या आईटीआर-4 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

आईटीआर-3 आमतौर पर उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा भरा जाता है, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है और जो सरल फॉर्म के पात्र नहीं हैं। आईटीआर-4 (सुगम) पात्र निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) के लिए है, जो अनुमानित कराधान योजना (एओपी) आदि पर लागू होता है, जबकि आईटीआर-7 विशेष प्रावधानों के तहत आने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के लिए है।

जिन करदाताओं के व्यवसाय या पेशे के खातों का टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। आमतौर पर कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक होने पर आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होता है।

नई कर व्यवस्था में 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता। पुरानी व्यवस्था में 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सीमा 2.5 लाख रुपये, 60 से 79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपये है।

कुछ मामलों में आय छूट सीमा से कम होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनमें विदेश में संपत्ति होना, विदेशी संपत्ति का लाभार्थी होना, विदेशी बैंक खाते में हस्ताक्षर का अधिकार या विदेश में वित्तीय हित शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष में निर्धारित उच्च-मूल्य लेनदेन करने या कटौतियों-छूट (जैसे धारा 80सी से 80यू या धारा 54) का लाभ लेने से पहले कुल आय मूल सीमा से अधिक होने पर भी आईटीआर अनिवार्य है। (इनपुट-एजेंसी)

वैश्विक बदलावों के बीच भारत अपनी विकास गति बनाए रखने में सक्षम -वित्त मंत्री सीतारमण

मुंबई ■ एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी ग्रोथ की रफ्तार को कम किए बिना ग्लोबल इकॉनमी में हो रहे बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। उन्होंने देश की आयातित ऊर्जा और फर्टिलाइजर पर निर्भरता को भी स्वीकार किया। जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने भारत को चुनौतियों से निपटने में सक्षम अर्थव्यवस्था बताया।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। भारत कुछ घरेलू उत्पादन क्षमता होने के बावजूद कई उर्वरकों और उनके कच्चे माल का भी आयात करता है।

वित्त मंत्री ने कहा, हम कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े आयातकों में से एक हैं। हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों (यूरिया, अमोनिया, डीएपी) के बड़े आयातक हैं। देश के भीतर उत्पादन क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद हम आयातक हैं।निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के आर्थिक प्रदर्शन ने यह दिखाया है कि वह विदेशों में होने वाले घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने और अपनी ग्रोथ की गति को बचाए रखने में सक्षम है। उन्होंने कहा, च्ये सभी एक जीवंत अर्थव्यवस्था के बहुत स्पष्ट संकेत हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर बदलावों को स्वीकार करती है और खुद को इस तरह से ढालती है कि हमारी ग्रोथ प्रभावित न हो।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी समय-समय पर अर्थव्यवस्था का अपना आकलन जारी करता है, जिसमें संकेतक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, च्हां, चुनौतियां हैं, और हम सरकार के तौर पर हर बार चुनौती आने पर भारत को फायदेमंद स्थिति में लाने के लिए काम करेंगे ।ज्ज् भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे लगातार बाहरी दबावों के बीच हासिल किया गया है। उन्होंने कहा, च्इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी इस वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो यह दिल को सुकून देने वाला है कि लोगों की मेहनत रंग ला रही है ।ज्ज् केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह विस्तार किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। जीडीपी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। वित्तीय क्षेत्र और पेशेवर सेवा क्षेत्र 12.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं।

वित्त मंत्री के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 अरब डॉलर पर है। उन्होंने कहा, च्ये कोई सामान्य आंकड़े नहीं हैं ।ज्ज् वित्त मंत्री सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय नागरिकों, आर्थिक सुधारों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली ने छोटे, सूक्ष्म और मध्यम व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद की है। निर्मला सीतारमण ने कहा, च्जिस तरह से डिजिटलीकरण ने छोटे, सूक्ष्म, मध्यम व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद की है, यूपीआई, एनपीसीआई, क्यूआर कोड और बाकी सब की गहरी पैठ के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती सामने आई है। वित्त मंत्री ने कारोबार को आसान बनाने के उपायों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकारों को भी श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि 1,000 से अधिक कानूनों को हटाया गया है और लगभग 40,000 नियमों को सरल बनाया गया है। सरकार उद्योग, व्यवसाय और व्यापार के साथ अपना जुड़ाव जारी रखे हुए है, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और निवेशक संरक्षण समझौतों पर भी काम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशी जमा और विदेशों में भारतीयों द्वारा किए गए निवेश भी देश की बैंकिंग प्रणाली और व्यापक आर्थिक संकेतकों में विश्वास को दर्शाते हैं।

वित्त मंत्री इस समय जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए एशविले में हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी अध्यक्षता के विकास, वैश्विक असंतुलन और वित्तीय साक्षरता पर फोकस का समर्थन करता है और इन मुद्दों पर च्चिष्पक्ष, खुली चर्चाज् चाहता है। उन्होंने अमेरिका, पोलैंड, कतर, दक्षिण कोरिया और रूस के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। जी20 बैठक के बाद वह भारत में रुचि रखने वाले निवेशकों के साथ बैठकों के लिए न्यूयॉर्क जाएंगी।

समय रैना के बिहारी जोक विवाद पर मनोज बाजपेयी की दो टूक बोले - खुद पर हंसना सीखें

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कॉमेडी और संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर बहस छिड़ जाती है। हाल ही में समय रैना के शो पर हुए एक मजाक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा देखने को मिला था। अब इस पूरे मामले पर अपनी जड़ों से जुड़े अभिनेता मनोज बाजपेयी ने आगे आकर खुलकर बात की है और लोगों को परिपक्वता दिखाने की सलाह दी है।एक इंटरव्यू के दौरान जब मनोज बाजपेयी से समय रैना और शेरन वर्मा के बीच हुए जोक और उस पर उठे विवाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बात सिर्फ हंसी-मजाक तक सीमित है, तब तक किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा, अगर यह सब मजाक में है, तो मुझे वास्तव में इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें खुद पर हंसना सीखना चाहिए, एक-साथ मिलकर हंसना चाहिए और फिर भी आहत या अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। अभिनेता ने आगे कहा कि हमारे अंदर खुद पर हंसने का हुनर होना चाहिए, लेकिन साथ ही सामने वाले व्यक्ति और उसकी पृष्ठभूमि के प्रति भी पूरा सम्मान होना चाहिए।अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मनोज बाजपेयी ने अपने शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प वाकया याद किया जब वह 18 साल की उम्र में नए-नए दिल्ली आए थे। उन्होंने बताया, जब मैं दिल्ली में था, तब मैं 18 साल का था और पहली बार बस के सामने वाले गेट से चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे शहर के नियम नहीं पता थे। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर कहा ए बिहारी, पीछे वाले गेट से चढ़ो। उस समय उसे नहीं पता था कि मैं वाकई बिहार से हूं।उन्होंने आगे कहा कि उस ड्राइवर के लिए हर वो शख्स जो ऐसी नादानी कर रहा था, वह बिहारी जैसा लग रहा था। मनोज ने कहा कि उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि एक तो वह सचमुच बिहार से थे और दूसरा वह शहर में नए थे इसलिए गलती होना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि अलग-अलग रायों के दोस्तों के साथ रहने पर हम अक्सर एक-दूसरे की आदतों पर हंसते थे, लेकिन कभी ठेस नहीं पहुंचते थे।अपनी बात को खत्म करते हुए मनोज बाजपेयी ने जोर देकर कहा कि जब तक कोई चीज किसी समुदाय के लिए बड़ा संकट या नुकसान नहीं बन जाती, तब तक छोटी-मोटी बातों पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हमें एक-दूसरे पर और खुद पर हंसने की क्षमता रखनी चाहिए। यह एक बेहद स्वस्थ समाज की निशानी है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के एक सेगमेंट से हुई थी, जहां समय रैना और शेरन वर्मा ने एक-दूसरे की पृष्ठभूमि पर हल्के-फुल्के अंदाज में कटाक्ष किए थे। दूसरी ओर, वर्कफ्रंट की बात करें तो मनोज बाजपेयी जल्द ही फिल्म लास्ट मैन इन टॉवर में नजर आने वाले हैं, जिसका निर्देशन बेन राखी ने किया है और इसमें बोमन ईरानी तथा दिव्या दत्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं।

कियारा आडवाणी का व्हाइट साड़ी लुक हुआ वायरल 78 कैरेट के रूबी नेकलेस ने खींचा सबका ध्यान

कियारा आडवाणी की गिनती बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में होती है। उन्हें अपने फैशनेबल अंदाज के लिए भी पहचाना जाता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस को मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए एक आउटफिट में देखा गया। आप मेरे साथ फीट के साथ उन्होंने रुबी नेकलेस पहना था जिसमें उनका लुक बहुत ही कमाल का लग रहा था। एक्ट्रेस ने बहुत ही खूबसूरत सी सफेद शिफॉन साड़ी पहनी थी। जिस पर रूबी का नेकलेस उन्हें परियों की किसी राजकुमारी की तरह लुक दे रहा था। सादगी से भरा लेकिन यह स्टनिंग अंदाज फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहा। फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से कियारा आडवाणी का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें एक्ट्रेस ने सफेद रंग की शिफॉन साड़ी पहन रखी है। इसे उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रेप किया था। साड़ी का पल्लू हाथ और कंधे के ऊपर था। फिट कॉरसेट ब्लाउज के साथ यह काफी अच्छी लग रही थी। डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला यह डिजाइन सॉफ्ट और मॉडर्न दोनों ही टच देने का काम कर रहा था। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक्ट्रेस के लुक के बारे में पूरी जानकारी शेयर की है। वीडियो शेयर करते हुए डिजाइनर ने लिखा खूबसूरत कियारा आडवाणी, इन्होंने एक लहराती हुई सफ़ेद शिफॉन साड़ी पहनी है। इसके साथ उन्होंने एक क्लासिक नेकलेस पहना है, जिसमें 78 कैरेट से ज़्यादा मोज़ाम्बिक और बर्मी रूबी जड़े हैं। यह नेकलेस गहरे लाल फूलों की तरह दिखता है, जिसे हीरे जड़ी पत्तियों के डिज़ाइन से खूबसूरती से सजाया गया है और इसे 18ख्य सोने में तैयार किया गया है। उनकी इस पोस्ट पर कई सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। एक्ट्रेस की यह साड़ी तो बहुत सुंदर लग ही रही थी लेकिन इस लोक में सबसे ज्यादा चर्चा उनके स्टेटमेंट रुबी नेकलेस की हो रही है। मनीष मल्होत्रा न्यू जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस नेकलेस में 78 कैरैट से ज्यादा के मोजाम्बिक और बर्मीज रूबी का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें गोल्ड में फ्रेम किया गया है। व्हाइट साड़ी पर जरूरी काफी सुंदर लग रहा है। अपने इस लुक के साथ कियारा ने बालों के डीप साइड पार्टिंग कर रखी थी। स्मोकी आईज, डिफाइंड आइब्रो, सॉफ्ट रोज़ लिप मेकअप उनके ओवरऑल लुक को सुंदर बना रहे थे। एक्ट्रेस की साड़ी और ज्वेलरी दोनों ही बहुत ग्लैमरस थी इसके बावजूद भी उनका लुक काफी सिंपल नजर आ रहा था।

जैकलीन से जलती थीं नोरा फतेही

सुकेश की वायरल चिट्ठी में चौंकाने वाले दावे

200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनके साथ एक्ट्रेस नोरा फतेही भी चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर सुकेश चंद्रशेखर के नाम से लिखी गई एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने नोरा फतेही को लेकर कई गंभीर और चौंकाने वाले दावे किए हैं। इस कथित चिट्ठी में सुकेश ने नोरा और जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े अपने विवाद का भी जिक्र किया है। सुकेश ने अपने पत्र में दावा किया है कि नोरा फतेही उनके और जैकलीन फर्नांडिस के कथित रिश्ते से जलती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि नोरा उन्हें लगातार फोन किया करती थीं और बार-बार जैकलीन से दूरी बनाने के लिए कहती थीं। सुकेश के इन दावों के बीच यह चिट्ठी ऐसे समय सामने आई है, जब नोरा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस पूरे विवाद के कारण उन्हें हुई मानसिक परेशानी और तनाव के बारे में बात की थी।

कथित तौर पर सामने आई चिट्ठी में सुकेश ने दावा किया कि नोरा फतेही उन्हें दिनभर फोन किया करती थीं। उनके मुताबिक, नोरा बार-बार उनसे कहती थीं कि वह जैकलीन को छोड़ दें और उनके साथ रिश्ता खत्म कर लें। सुकेश ने यह भी दावा किया कि नोरा उनसे अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए कहती थीं।चिट्ठी में सुकेश ने कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया कि नोरा उनसे महंगे गिफ्ट्स की मांग करती थीं। उन्होंने बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारों के साथ-साथ महंगे बैग्स की मांग किए जाने का दावा किया है। हालांकि, ये सभी बातें सुकेश चंद्रशेखर की ओर से किए गए दावे हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से तथ्य के तौर पर स्थापित नहीं माना जाना चाहिए।सुकेश ने अपनी कथित चिट्ठी में नोरा को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोरक्को के कैसाब्लांका में नोरा के लिए एक घर खरीदने के लिए कथित तौर पर करोड़ों रुपये दिए थे। पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए नोरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।सुकेश ने कथित तौर पर नोरा को यह चेतावनी भी दी कि वह खुद को पीड़ित दिखाने का कथित नाटक बंद करें। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके पास दोनों के बीच हुई बातचीत से जुड़े और भी सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वह इन बातचीत और सबूतों को सार्वजनिक कर सकते हैं।सुकेश की कथित चिट्ठी सामने आने के बाद नोरा फतेही का हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू भी चर्चा में आ गया है। इस बातचीत में एक्ट्रेस ने उस विवाद के दौरान झेली गई मानसिक परेशानी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि विवाद और लगातार सामने आने वाली खबरों का उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा था।अब सुकेश की ओर से सामने आई इस कथित चिट्ठी ने एक बार फिर पुराने विवाद को चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि, चिट्ठी में किए गए आरोपों को लेकर संबंधित पक्षों के बयानों और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड को ही अंतिम आधार माना जाना चाहिए।

इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

इस वीक ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त पिटारा खुल रहा है. दरअसल ताम प्लेटफॉम पर अलग-अलग जॉनल की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं इनमें %गंधारी%, %बिग बॉस 20%, कोरियन कनकराजु से लेकर 'धमाल 4' तक शामिल है . इसी के साथ ओटीटी सब्सक्राइबर्स को जबरदस्त ड्रामा, कॉमेडी, सुपरनैचुरल ट्विस्ट और रियलिटी शो के कड़े चैलेंज देखने को मिलेंगे, जिससे ये पूरा वीक काफी मजेदार रहने वाला है. तो चलिए यहां 31 अगस्त से 6 सितंबर तक ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

धमाल 4

अजय देवगन की कॉमेडी एडवेंचर फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. खबरें हैं कि ये फिल्म 4 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इंद्र कुमार निर्देशित धमाल 4 में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा सहित कई कलाकार अहम रोल में नजर आएंगे. हांलांकि मेकर्स द्वारा इसकी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म होना अभी बाकी है.

बिग बॉस 20

मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस अपने बीसवें सीजन के साथ कमबैक कर रहा है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में सर्वाइवल टास्क, चुनौतियां, अनोखे रहस्य और गेम के नए तौर-तरीके देखने को मिलेंगे. बिग बॉस 20 जियो हॉट स्टार पर 6 सितंबर से देख सकेंगे.

गांधारी

तापसी पन्नू की एक्शन-थ्रिलर गांधारी एक दृष्टिहीन मां की कहानी है, जो अपनी अगवा की गई बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है. इस जबरदस्त फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 3 सितंबर से देख सकते हैं.

कोरियन कनकराजु

यह तेलुगु हॉरर-कॉमेडी और एक्शन फिल्म ग्रामीण आंध्र प्रदेश की संस्कृति और कोरियन सुपरनैचुरल एलीमेंट्स का ब्लेंड है. इसकी कहानी कनकराजु (वरुण तेज) नाम के एक गुस्सैल युवक की है, जिसे चैत्रा (रितिका नायक) से प्यार हो जाता है. चैत्रा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करती है और दक्षिण कोरिया जाने का सपना देखती है. इसे नेटफ्लिक्स पर 4 सितंबर से देख सकेंगे.

द कोर्ट

यह एक तमिल वेब सीरीज है जो याझिनी (योगलक्ष्मी का किरदार) नाम की एक होनहार युवा वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हकलाने की समस्या से जूझ रही है. वह एक अदालती लड़ाई में फँस जाती है, जहां उसे अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है. इसे भी 4 सितंबर से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

जगमे संगीतम

प्राइम वीडियो की अपनी हिंदी ओरिजिनल सीरीज़ बंदिश बैंडिट्स से इंस्पायर आठ एपिसोड वाला यह तेलुगु म्यूजिकल ड्रामा गोदावरी नदी के किनारे बसे पवित्र मंदिर शहर वैकुंठपुरम पर बेस्ड है. बालू (अक्षय लगुसानी), शास्त्री गारू (प्रकाश राज) का प्रतिभाशाली पोता है. शास्त्री गारू एक सम्मानित कर्नाटक संगीतकार हैं, जिनका प्रभाव बालू के हर काम पर दिखता है. जब बालू की मुलाक़ात कविता (सुष्मिता शेट्टी) से होती है, जो शोहरत से ऊब चुकी एक पॉप सिंगर है तो उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। यह रिश्ता शास्त्री की उस सदियों पुरानी विरासत के लिए खतरा बन जाता है, जिसे बचाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी. इसमें मेका श्रीकांत, मधुबाला, सुमन, सिजू मेनन और शफ़ी भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसे 4 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकेंगे.

उन्मदम

मलयालम फिल्म उन्मदम 4 सितंबर, 2026 से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी. इसमें कुंचाको बोबन और लिजोमोल जोस मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी शेली के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक निराश सिविल पुलिस अधिकारी है और साथ ही स्क्रीनराइटर बनने का सपना भी देखता है. अपनी स्क्रिप्ट के लिए एक आइडिया की तलाश करते समय, वह एक युवा महिला की रहस्यमयी मौत से जुड़े एक पुराने केस को फिर से खोलने का फैसला करता है.

द जेंटलमैन सीजन 2

द जेंटलमैन सीजन 2 को 3 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. गाय रिची की बनाई यह क्राइम कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़, अमीर परिवार के सदस्य एडी और उसके परिवार की जागीर से जुड़ी अजीबोगरीब क्रिमिनल दुनिया की कहानी को आगे बढ़ाती है. इस शो में क्राइम, डार्क ह्यूमर और मुश्किल हालात देखने को मिलते हैं, जिसमें किरदार अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं.

लव सिक

1910 के दशक में मेक्सिको की राजनीतिक क्रांति के दौर पर आधारित यह सात एपिसोड का पीरियड ड्रामा, एक ताकतवर परिवार की युवा महिला वियोलेटा (रेनाटा वाका) की कहानी है। उसकी ज़िंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसे एमिलियानो (जुआन पाब्लो फुएंटेस) से प्यार हो जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 2 सितंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

टर्निंग पॉइंट- जनरेशन 9/11

11 सितंबर के हमलों के 5 साल बाद, आधे से ज़्यादा अमेरिकी या तो 2001 के बाद पैदा हुए थे या इतने छोटे थे कि उन्हें वे हमले याद नहीं थे. फिर भी, उस एक दिन का असर आज भी उनकी ज़िंदगी को साफ़ और छिपे हुए, दोनों तरह से प्रभावित कर रहा है. ब्रायन नैपेनबर्गर की मशहूर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ टर्निंग पॉइंट की यह चौथी फिल्म है. ये उन लोगों की नजर से उस लंबे असर को दिखाती है जिन्होंने इसे झेला है. ये नेटफ्लिक्स पर 2 सितंबर से स्ट्रीम होगी।

पुरा छात्रों ने याद किए स्कूल वाले दिन हुए भावुक

साधना एक्सप्रेस रीवा

शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडोटोरियम में जब देश के विभिन्न कोने से 30 अगस्त को भारी बारिश के बावजूद 500 से अधिक नवोदयन नवोदय संगम 3.0 में इकट्ठे हुए । रीवा नवोदय के अलावा सीधी , सतना सहित लगभग विंध्य के प्रत्येक नवोदय से एलुमनाई पहुंचे हुए थे । मध्यप्रदेश से लेकर बिहार , छत्तीसगढ़ और पंजाब तक के पुरा छात्र मौजूद रहे।कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना तत्पश्चात नवोदय प्रार्थना को सभी नवोदयन एक लय में गुनगुनाए। मिलाप , नवरंग , मंथन और सहयोग के माध्यम से नवोदय के 7 साल की खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए हर किसी ने अपना सुझाव दिया । संगम 3.0 के इस भव्य आयोजन में NAAV नवोदय एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ विंध्य - भारत की आधिकारिक घोषणा हुई। सभी नवोदयन सुबह 9 से सायं 6 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जुड़े रहे और विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए नवोदय के लिए और किस प्रकार से भविष्य में जुड़कर नवोदय के लिए खुद को समर्पित कर सकते है पर जोर डाला । कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र को साहित्यिक व हास्य व्यंग कविताओं से गौरवान्वित करने वाले कवि आशीष तिवारी निर्मल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन मंयक तिवारी ने किया।

पीएम श्री हाईस्कूल भटेरा में लाखों के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप, सरपंच ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(राजेश नीरस) एक प्रसिद्ध कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या ग्राम पंचायत भटेरा के पीएम श्री हाईस्कूल में स्वीकृत निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार और शासकीय राशि के गबन का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत भटेरा के सरपंच राजू लोधी ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

सरपंच द्वारा दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम भटेरा के पीएम श्री हाईस्कूल में शासन द्वारा तीन निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। जिसमें शौचालय निर्माण हेतु 14.60 लाख रुपये, अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 16.00 लाख रुपये और खेल मैदान निर्माण हेतु 5.00 लाख रुपये शामिल हैं। आरोप है कि ठेकेदार अतुल गुबरेले द्वारा इन निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता बरती गई है और शासन की राशि का गबन किया गया है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि ठेकेदार के पिता ही स्कूल के प्राचार्य हैं, जिसके चलते निर्माण कार्यों में मनमानी की जा रही है।

सरपंच ने बताया कि हाईस्कूल भटेरा में स्वीकृत तीनों में से एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। शौचालय और खेल मैदान का कार्य तो शुरू ही नहीं किया गया है, जबकि अतिरिक्त कक्ष का कार्य भी अधूरा पड़ा है। इसके बावजूद लाखों रुपये की राशि आहरित कर ली गई है। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत भटेरा में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में भी ग्रामवासियों ने निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है। सरपंच राजू लोधी ने मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री को भी आवेदन प्रेषित कर पीएम श्री हाईस्कूल भटेरा के निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

अतिवृष्टि में बही अटरिया के पास पुलिया, आवागमन प्रभावित

बैकुंठपुर–फूल देवास–लालगांव मार्ग पर ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, जिम्मेदारों से मरम्मत की मांग

साधना एक्सप्रेस लालगांव

लगातार हुई अतिवृष्टि के चलते बैकुंठपुर से फूल देवास होते हुए लालगांव जाने वाले मार्ग पर अटरिया के समीप बनी पुलिया तेज बारिश के पानी में बह गई। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों एवं राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान जलभराव और तेज बहाव के कारण पुलिया का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर बह गया। मार्ग बाधित होने से आसपास के गांवों के लोगों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दैनिक आवागमन, स्कूल, बाजार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इस मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण और रखरखाव को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। अटरिया के पास पुलिया का अतिवृष्टि में बह जाना निर्माण की गुणवत्ता और बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है।

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग एवं जनप्रतिनिधियों से मौके का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त पुलिया की तत्काल मरम्मत कराने तथा आवागमन बहाल करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए पुलिया और मार्ग की तकनीकी जांच कर स्थायी समाधान किया जाना आवश्यक है।

गौ सेवकों की बैठक सम्पन्नए गो सम्मान, गो-सेवा में जुटे सेवकों का हुआ सम्मान

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(राजेश नीरस) गौमाता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर गाडरवारा में गौ सेवकों की बैठक नगर के गायत्री मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र में निरंतर गौ सेवा के कार्य में जुटे गौ सेवकों के सेवाभावी कार्यों की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया गया।

इस अवसर पर अंश बोहरे, रौनक बोहरे, प्रियांशु पिपरोनिया, पवन पाल एवं सौरभ ठाकुर, मोनू राजपूत को समर्पित,निरंतर गौ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से सड़कों पर विचरण एवं बैठने वाली लावारिस गौमाताओं के सुरक्षित एवं व्यवस्थित विस्थापन, जिले की गौशालाओं की नियमित निगरानी तथा गौमाताओं के लिए भोजन, पानी और उचित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में जिले में संचालित 81 गौशालाओं को 8 मंडलों में विभाजित कर प्रत्येक मंडल में 5-5 गौभक्तों की टीम गठित करने पर सहमति बनी। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्र की गौशालाओं की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी एवं निरीक्षण करते हुए वहां गौमाताओं के खान-पान, पानी, स्वच्छता, रखरखाव एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करेंगी तथा किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित प्रशासन एवं गौशाला प्रबंधन के संज्ञान में विषय लाने का कार्य करेंगी।बैठक में उपस्थित गौ सेवकों ने एक स्वर में कहा कि सड़कों पर रहने वाली गौमाताओं को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से गौशालाओं तक पहुंचाने की ठोस व्यवस्था आवश्यक है। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह भी तय किया गया कि गाडरवारा एवं जिला नरसिंहपुर में स्थित मंदिरों की भूमि पर मंदिर प्रबंधन एवं जनभागीदारी के माध्यम से गोधाम, गौशाला अथवा गो-अभ्यारण्य जैसे गौ सेवा प्रकल्प संचालित करने के लिए गौ सेवकों द्वारा मंदिर प्रबंधनों को प्रेरित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य मंदिरों से गौ सेवा को जोड़ते हुए गौमाता के सेवा, सम्मान, संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देना है।

साथ ही ऐसे प्रकल्पों के माध्यम से मंदिरों में गौमाता के शुद्ध दूध, दही, घी आदि से निर्मित प्रसाद तैयार कर भगवान को भोग लगाने की परंपरा को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा।

बैठक में जिले में लगने वाले मवेशी बाजारों को लेकर भी चर्चा हुई। गौ सेवकों द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं जनभागीदारी के सहयोग से बाजार में आने-जाने वाले मवेशियों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से सतत निगरानी सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य किए जाने पर सहमति बनी।

इसका उद्देश्य मवेशियों के आवागमन की पारदर्शी निगरानी, किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी संबंधित प्रशासन तक पहुंचाना तथा गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करना रहेगा।

प्रातः स्मरणीय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी(द्वारका मठ गुजरात) के प्रिय शिष्य, महाकोशल युवा संत मार्ग दर्शक मंडल के सदस्य एवं गोसम्मान आव्हान अभियान के जबलपुर संभाग प्रभारी तथा गो सेवक, राष्ट्रीय कथाकार उमा-महेश नंदन आचार्य मनीष जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में गौ सम्मान आव्हान अभियान के तीसरे चरण को सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर गाडरवारा के गायत्री मंदिर में विस्तृत चर्चा की गई। गौ सम्मान आव्हान अभियान के तीसरे चरण में राजधानी स्तर पर 17 दिसंबर 2026 को भोपाल में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे। जिसमें तहसील के सभी गौ भक्तों, गौ सेवकों एवं गो पालकों को भोपाल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाकर गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना एवं पूरे देश से गौ हत्या बंद करवाकर गौ मंत्रालय बनाना मुख्य मांग है। इस अभियान के तीसरे चरण में ग्रामीण स्तर एवं पंचायत स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर अधिक से अधिक हस्ताक्षर करवाना है एवं एक ग्राम से लगभग 21 गो सेवकों की टीम को तैयार कर 17 दिसंबर को आवश्यक रूप से भोपाल पहुंचना है। इसके लिए ग्रामों में जाकर ग्राम के मुखिया सरपंच महोदय से संपर्क कर अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाना है एवं भोपाल चलने के लिए आग्रह करना है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में सतीश लमानिया,महेंद्र भार्गव, रमाकांत शुक्ला, राजा शर्मा,भगवान दास चढ़ार,कार्तिक भार्गव, मोनू राजपूत, प्रेम तिवारी, विवेक कुरचनिया, खेत सिंह पटेल, पंचम सिंह गुर्जर, मोतीलाल शर्मा, राजकुमार केवट, रामदास यादव, मूलचंद पटेल, मनोज द्विवेदी, रामशरण सिंह कौरव, स्नेहलता दीदी, आशीष शर्मा एवं भरत कौरव सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक उपस्थित रहे।

अंत में सभी गौ सेवकों ने गौमाता की सुरक्षा, सेवा, सम्मान, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर सक्रिय रहकर जनभागीदारी एवं प्रशासन के सहयोग से कार्य करने का संकल्प लिया।

समाजसेवी फलित सिंह पटेल के नेतृत्व में झामर से धमना तक निकली 11 किमी की 'युवा जागरण पदयात्रा..नशा मुक्ति अभियानः 100 दिवसीय जनजागरण संकल्प का चौथा सप्ताह पूर्ण, गांव-गांव पहुंचा 'नशामुक्त युवा–सशक्त समाज' का संदेश

साधना एक्सप्रेस नरसिंहपुर

'माई भारत' नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत सहयोग युवा समिति द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज में नशामुक्ति के प्रति जनचेतना बढ़ाने के उद्देश्य से 'युवा जागरण पदयात्रा' का आयोजन किया गया। समाजसेवी फलित सिंह पटेल के नेतृत्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झामर से सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमना तक निकली इस पदयात्रा ने लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय की उल्लेखनीय है कि फलित सिंह पटेल ने युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने और उन्हें इस सामाजिक अभियान से जोड़ने के लिए 100 दिवसीय जनजागरण का संकल्प लिया है। युवा जागरण पदयात्रा के आयोजन के साथ इस संकल्प का चौथा सप्ताह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ अभियान के पिछले तीन सप्ताहों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और विद्यालयों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं एवं युवाओं से लगातार संवाद किया गया। उन्हें तंबाकू, शराब एवं अन्य नशों से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए स्वयं नशा न करने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई

इसी जनजागरण को विद्यालयों से आगे गांव और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से झामर से धमना तक युवा जागरण पदयात्रा निकाली गई।

पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों, स्थानीय नागरिकों एवं सहयोग युवा समिति के सदस्यों ने सहभागिता की। हाथों में नशामुक्ति एवं युवा जागरण के संदेश वाली तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने "युवा जागेगा–नशा भागेगा", "नशे को ना–जीवन को हां" और "नशामुक्त युवा–सशक्त भारत" जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करीब 11 किलोमीटर के मार्ग में आने वाले गांवों, बस्तियों और शिक्षण संस्थानों में ग्रामीणों एवं युवाओं से सीधा संवाद किया गया।

लोगों को नशे के कारण व्यक्ति के साथ परिवार और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई गई। क्षेत्रवासियों ने भी पदयात्रा का स्वागत करते हुए अभियान में सहभागिता का आश्वासन दिया इस अवसर पर फलित सिंह पटेल ने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ अपने मित्रों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि युवा स्वयं नशामुक्ति का संकल्प लेकर समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी संभालें, तभी नशामुक्त और सशक्त समाज का निर्माण संभव होगा सहयोग युवा समिति ने बताया कि 100 दिवसीय संकल्प के आगामी सप्ताहों में भी विद्यालयों, गांवों और सार्वजनिक स्थानों पर संवाद, युवा सहभागिता एवं विभिन्न जनजागरण गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी अभियान का लक्ष्य युवाओं को नशामुक्ति का संदेशवाहक बनाकर 'नशामुक्त युवा से नशामुक्त समाज' की सोच को जनआंदोलन का स्वरूप देना है।

स्कूलों में दिखाया गया लेपटॉप वितरण राशि कार्यक्रम का प्रसारण

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(राजेश नीरस) विगत दिवस मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप क्रय हेतु 304 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री यादव ने कुछ विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से लैपटॉप भी वितरित किए, उनसे संवाद किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को क्षेत्र के चीचली ब्लॉक अंतर्गत सालीचौका के शासकीय कन्या उ मा विद्यालय एवं सूखाखैरी के शा उ मा विद्यालय सहित जिले सहित क्षेत्र के अन्य स्कूलों में भी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति में देखा गया। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ अनिल कुशवाहा द्वारा जारी आदेशानुसार साईखेड़ा के छात्र आदित्य कुशवाहा शिक्षक सिराज अहमद सिद्धिकी एवं नरसिंहपुर की छात्रा माही साहू शिक्षक श्रीमती विनीता सराठे के साथ शामिल हुए थे एवं इस आयोजन में विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु प्राचार्य प्रभात मिश्रा को नोडल अधिकारी बनाया गया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मिनाक्षी पांडेय द्वारा डीके ऑफसेट प्रिंटर्स 50/6 शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से मुद्रित एवं 111/44, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से प्रकाशित ।
संपादक मिनाक्षी पांडेय एवं स्थानीय संपादक मनीष पांडेय मो.न- 7566293490, प्रबंध संपादक आशीष नेमा मेल sadhnaexpress@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र रहेगा ।)| RNI NO. MPHIN/2022/84698